https://www.facebook.com/KamalSandeshBjp/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

24 विमुद्रीकरण
काले धन पर कड़ा प्रहार

वर्ष-11, अंक-24, 16-31 दिसंबर, 2016 (पाक्षिक) ₹20

जनजागरण महासमावेश, ओडिशा

विमुद्रीकरण पर विपक्ष बेनकाब

महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में खिला कमल | खिसियाये दल सड़क से संसद तक छाती पीट रहे हैं | पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद बड़ा खतरा

पार्टी पत्रिकाएं एवं प्रकाशन विभाग की राष्ट्रीय बैठक की अध्यक्षता करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह; इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री रामलाल भी उपस्थित थे

भाजपा मुख्यालय में 6 दिसंबर 2016 को डॉ. भीमराव अम्बेडकर के महा-परिनिर्वाण दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in
mail@kamalsandesh.com
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **नवीनजी, आपने 17 सालों में राज्य के विकास के लिए क्या किया**
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने भुवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजित जन जागरण महा समावेश को संबोधित किया और उड़ीसा की बदहाली पर राज्य की नवीन पटनायक सरकार पर...

वैचारिकी
भारत का ग्रामीण समाज एवं अन्त्योदय 14

श्रद्धांजिल
भाई महावीर नहीं रहे 16

मन की बात
देश सोने की तरह तप कर निखरेगा 22

लेख
खिसियाये दल सड़क से संसद तक छाती पीट रहे हैं 24
विमुद्रीकरण काले धन पर कड़ा प्रहार 26
मृदा स्वास्थ्य कार्ड से मिट्टी की उर्वरकता फिर से प्राप्त करने में मदद मिलेगी 28

परिवर्तन रैलियां
कुशीनगर (उ.प्र.) 18
महाराजगंज (उ.प्र.) 19
कारूकुट्टी (केरल) 20
मुरादाबाद (उ.प्र.) 21

अन्य
विमुद्रीकरण का रबी की बुआई पर कोई असर नहीं 17
किसान रैली : टेडपल्लीगुडम (आंध्रप्रदेश) 30
ओबीसी मोर्चा रैली : बेंगलुरु (कर्नाटक) 31
पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद बड़ा खतराः भारत 32

संगठनात्मक गतिविधियां

08 महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में खिला कमल
कभी-कभी ऐतिहासिक फैसलों पर देश की जनता की पसंदगी-नापसंदगी मापने का...

10 'संगठन विस्तार में पार्टी पत्रिकाओं की अहम भूमिका'
नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में 6 दिसम्बर 2016 को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष...

सरकार की उपलब्धियां

11 लोकसभा में कराधान विधि विधेयक, 2016 पारित
लोकसभा में 29 नवंबर को कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक ध्वनि मत से...

13 ई-पशु हाट पोर्टल का शुभारम्भ
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने 26 नवंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@JPNadda

हरिद्वार की पवित्र भूमि पर उतरा जनसमूह उत्तराखंड में आने वाले परिवर्तन का द्योतक है। 'अबकी बार भाजपा सरकार'।

@PiyushGoyal

हम दीनदयाल उपाध्याय जी के बताये मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, हम मनुष्य की प्रगति और प्रसन्नता के लिये कार्य करते हैं।

@dpradhanbjp

रोजाना 4 करोड़ ग्राहक के साथ पेट्रोलियम क्षेत्र आनेवाले दिनों में सभी सफल उपलब्धियों की आधारशिला बनेगा।

@rsprasad

वे यात्री जो 'डिजिटल पेमेंट्स के जरिए ऑनलाइन रेलवे टिकट खरीदेंगे, उन्हें 10 लाख का बीमा मुहैय्या होगा।

@PrakashJavdekar

'Timeshighered यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2016-17' की 1000 उत्कृष्ट यूनिवर्सिटियों में 31 भारतीय यूनिवर्सिटियों का नाम शामिल होना प्रसन्नता की बात है।

facebook

मैं भारत के लोगों को सलामी देता हूं, जिन्होंने पूरे मन से भ्रष्टाचार, आतंकवाद तथा कालेधन के खिलाफ 'यज्ञ' में हिस्सा लिया है। इस फैसले से किसानों, व्यापारियों और श्रमिकों को कई फायदे होंगे, जो 'हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। अब हमारे ग्रामीण भारत की प्रगति और समृद्धि भ्रष्टाचार और कालेधन की वजह से प्रभावित नहीं होगी। हमारे गांवों को उनका हक मिलना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि सरकार के उपाय से लोगों को कुछ असुविधा जरूर होगी। पर इस थोड़े समय के कष्ट से लंबे समय तक लाभ होगा। हमारे पास कैशलेस भुगतान को अपनाने का ऐतिहासिक अवसर है। साथ ही हम आर्थिक लेनदेन में ताजा प्रौद्योगिकी का एकीकरण कर सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि भारत कालेधन को हराए। इससे गरीब, नव मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग तथा भविष्य की पीढ़ियों का सशक्तीकरण होगा। **- नरेंद्र मोदी**

भाजपा संगठन और विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी है। भाजपा का प्राणतत्व है संगठन और संगठन का प्राणतत्व बूथ हैं। बूथ कार्यकर्ता भाजपा संगठन की रीढ़ की हड्डी हैं। केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सिर्फ बूथ कार्यकर्ता ही घर घर पहुंचा सकता है। कांग्रेस ने देश को कालेधन का लकवा दिया था जिसका श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने नोटबंदी से ऑपरेशन किया है। **- अमित शाह**

व्यंग्य चित्र

जनसत्ता

पाथेय

संस्कृति-प्रधान जीवन की यह विशेषता है कि इसमें जीवन के केवल मौलिक तत्वों पर तो जोर दिया जाता है पर शेष बाह्य बातों के संबंध में प्रत्येक को स्वतंत्रता रहती है। इसके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रत्येक क्षेत्र में विकास होता है। संस्कृति किसी काल विशेष अथवा व्यक्ति विशेष के बन्धन से जकड़ी हुई नहीं है, अपितु यह तो स्वतंत्र एवं विकासशील जीवन की मौलिक प्रवृत्ति है। इस संस्कृति को ही हमने धर्म कहा है। अतः जब कहा जाता है कि भारतवर्ष धर्म-प्रधान देश है तो इसका अर्थ मज़हब, मत या रिलीजन नहीं, किन्तु यह संस्कृति ही होता है।

-प. दीनदयाल उपाध्याय

कालेधन के कारोबारियों के साथ है विपक्ष

एक ओर जहां जन–जन का व्यापक समर्थन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 500/– और 1000/– रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण के निर्णय को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर दिनों–दिन कांग्रेस को यह बताना और भी मुश्किल होता जा रहा है कि आखिर वह संसद क्यों नहीं चलने दे रही है। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि सरकार किसी विषय पर संसद में चर्चा करने को तैयार हो और विपक्ष उस चर्चा से भाग रही हो। यह इससे भी स्पष्ट होता है कि जैसे ही सरकार कांग्रेस की एक मांग को मानती है, कांग्रेस दूसरी मांग रख देती है और इसी बहाने संसद को चलने नहीं दे रही है। कांग्रेस किसी ना किसी बहाने विमुद्रीकरण और काले धन पर चर्चा नहीं होने देना चाहती, ताकि उसका असली चेहरा देश के सामने पूरी तरह से उजागर ना हो जाय। लेकिन शायद वह इस बात को भूल रही है कि इस तरह से संसद के काम–काज को रोकने से उसका वही चेहरा सामने आ रहा है जिसे वह छुपाना चाहती है। स्थिति इस हद तक बिगड़ी है कि स्वयं राष्ट्रपति को अपील करनी पड़ी, पर कांग्रेस है कि वह संसद बाधित करने पर अड़ी हुई है।

कांग्रेस और इसके सहयोगियों के लिए विमुद्रीकरण का निर्णय एक बहुत बड़ा झटका है, जिससे वे उबर नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस साहसिक निर्णय का स्वागत एवं समर्थन करने के स्थान पर कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों ने काला बाजारियों, घोटालेबाजों एवं हवाला कारोबारियों के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। लोगों को गुमराह करने के लिए अनेक मिथक गढ़े गये तथा लोगों के दिमाग में आशंकाएं उत्पन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। यहां तक कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बैंकों में गये, पर परेशानियां झेलने के बावजूद कतारों में खड़े लोगों का समर्थन नहीं पा सके। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली तक आ पहुंची, परन्तु विपक्ष के अंदर न केवल अलग–थलग पड़ गई, बल्कि जनता का समर्थन प्राप्त करने में भी असफल रहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की तीन दिनों में निर्णय वापिस लेने की धमकी भी कोरी लफ्फाजी साबित हुई। संसद घेरने की उनकी मुहिम जनसमर्थन के अभाव में पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद से केजरीवाल के मुंह पर ताला लग चुका है। भारत बंद के दौरान भी कांग्रेस सहयोगियों और कम्युनिस्टों को देश की जनता ने अच्छा सबक सिखाया। भारत बंद फ्लॉप होता देख कांग्रेस और इसके सहयोगियों ने इससे किनारा कर लिया। बसपा सुप्रीमो मायावती भी उसके बाद से चुप हैं। वास्तविकता यह है कि प्रधानमंत्री के इस साहसिक निर्णय का विरोध करने वाली पार्टियां अब काले धन एवं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता के सामने बेनकाब हो चुकी हैं।

अब समय आ गया है जब देश की जनता परिवर्तन चाहती है, युवा साहसिक कदम देखना चाहते हैं, महिलाएं समान अवसर, गरीब बेहतर जिन्दगी, किसान नई तकनीक तथा शोषित–पीडि.त–लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं। नये युग की आकांक्षाओं को साकार करने के लिये यह आवश्यक है कि भ्रष्ट व्यवस्था जिसे कांग्रेस शासन ने पाला–पोषा और बढ़ाया है, उस पर प्रहार किया जाय।

काले धन के विरुद्ध लड़ाई में जिस प्रकार का जनसमर्थन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मिल रहा है, वह भारत के इतिहास में अपने–आप में अद्भुत है। इस निर्णय की आलोचना करने वाले लोग व्यापक जनसमर्थन देखकर हतप्रभ हैं। जो लोग इस कदम से भाजपा के आधार को खतरे में देख रहे थे, उन्हें विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनावों तथा गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में हुए स्थानीय निकायों के चुनावों के परिणामों से जनता का मूड समझ लेना चाहिए। ये परिणाम विपक्ष के लिए भी एक सबक है और कांग्रेस को समझना चाहिए कि बिचौलिये, घोटालेबाजों, हवाला कारोबारी, भ्रष्ट व्यवस्था एवं काले धन के बल पर वह जनता का समर्थन प्राप्त नहीं कर सकती। अब समय आ गया है जब देश की जनता परिवर्तन चाहती है, युवा साहसिक कदम देखना चाहते हैं, महिलाएं समान अवसर, गरीब बेहतर जिन्दगी, किसान नई तकनीक तथा शोषित–पीड़ित लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं। नये युग की आकांक्षाओं को साकार करने के लिये यह आवश्यक है कि भ्रष्ट व्यवस्था जिसे कांग्रेस शासन ने पाला–पोषा और बढ़ाया है, उस पर प्रहार किया जाय। इसलिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साहसिक एवं निर्णायक कदम उठा रहे हैं, जिसे जन–जन का अपार समर्थन मिल रहा है। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

नवीनजी, आपने 17 सालों में राज्य के विकास के लिए क्या किया : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने भुवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजित जन जागरण महा समावेश को संबोधित किया और उड़ीसा की बदहाली पर राज्य की नवीन पटनायक सरकार पर करारा प्रहार किया। उन्होंने प्रदेश भर में फैले भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि आप उड़ीसा के विकास के लिए 'अगली बार, भाजपा सरकार' का संकल्प लेकर पंचायत चुनाव में जाएं और मजबूत भाजपा की नींव रखें।

उड़ीसा के मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवीन पटनायक जी हमेशा पूछते रहते हैं कि केंद्र की भाजपा सरकार ने उड़ीसा के विकास के लिए क्या किया, मैं नवीन जी से पूछता हूं कि नवीन जी, आप ने 17 सालों में राज्य के विकास के लिए क्या किया, पहले इसका जवाब प्रदेश की जनता को दीजिये। उन्होंने कहा कि 17 वर्ष का कालखंड किसी राष्ट्र अथवा राज्य के लिए बहुत बड़ा कालखंड होता है, लेकिन इन 17 सालों में जहां भाजपा शासित राज्य विकास की नई इबारत लिख रहे हैं, वहीं उड़ीसा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ नहीं पाया है। उन्होंने कहा कि जो सरकार 17 सालों में राज्य के लोगों को पीने का पानी तक मुहैय्या नहीं करा पाई, वह और क्या कर सकती है? उन्होंने कहा कि उड़ीसा में आज भी इतनी ताकत है कि वह कोयले से पूरे हिन्दुस्तान को रौशन कर सकती है, लेकिन राज्य के 41% गांवों में आज भी बिजली नहीं पहुंच पाई है। उन्होंने कहा कि जो सरकार 17 सालों में लोगों को बिजली-पानी तक नहीं पहुंचा पाई, उस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं है। राज्य में बेरोजगारी की समस्या पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उड़ीसा में रोजगार की दिशा में कोई काम नहीं हुआ, हम ऐसा उड़ीसा बनाना चाहते हैं जहां युवाओं को रोजगार के लिए राज्य से पलायन को विवश न होना पड़े। उन्हें यहीं अपने परिवार के साथ रहते हुए रोजगार के अवसर प्राप्त हों, यदि 17 सालों में उड़ीसा सरकार ने सही तरीके से काम किये होते तो राज्य के युवाओं को नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। उन्होंने कहा कि उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार ने राज्य के जनजातियों की भी घोर उपेक्षा की है, आज भी जनजाती यदि सबसे ज्यादा कहीं पिछड़ा हुआ है तो वह उड़ीसा में है। राज्य में कृषि विकास की धीमी दर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कृषि के विकास के लिए केंद्र से जितना भी फंड उड़ीसा के लिए आता है, मालूम ही नहीं पड़ता कि कहां चला जाता है। उन्होंने कहा कि उड़ीसा सरकार किसानों के खेत की सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि यही हाल राज्य की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था का भी है।

17 वर्ष का कालखंड किसी राष्ट्र अथवा राज्य के लिए बहुत बड़ा कालखंड होता है, लेकिन इन 17 सालों में जहां भाजपा शासित राज्य विकास की नई इबारत लिख रहे हैं, वहीं उड़ीसा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ नहीं पाया है।

श्री शाह ने ढाई सालों में केंद्र सरकार द्वारा उड़ीसा के विकास

के लिए किये गए कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने उड़ीसा के लिए ढाई साल में जो किया है वह आजादी के बाद इन 70 सालों में भी किसी और सरकार ने नहीं किया है। सोनिया-मनमोहन सरकार से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि 2013 में केंद्र की यूपीए सरकार ने उड़ीसा के विकास के लिए लगभग 23,000 करोड़ रुपये आवंटित किया जबकि 2016 में भाजपा की मोदी सरकार ने उड़ीसा के लिए लगभग 63,000 करोड़ रुपया आवंटित किया है। हमने सोनिया-मनमोहन सरकार की तुलना में लगभग 40,000 करोड़ रुपया अधिक दिया है, इसी तरह राज्य में रेलवे के विकास के लिए 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 764 करोड़ रुपया दिया, वहीं भाजपा की मोदी सरकार ने 2016 के रेल बजट में उड़ीसा के लिए लगभग 4682 करोड़ रुपये आवंटित किये। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में राजमार्गों के विकास के लिए साल 2016 में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लगभग 45,000 करोड़ रुपये और ग्रामीण सड़क के निर्माण के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपये आवंटित किये गए। उन्होंने कहा कि राज्य में जल मार्गों के विकास की योजना भी केंद्र की भाजपा सरकार ने बनाई है। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी उड़ीसा के लगभग 3474 गांवों में बिजली नहीं पहुंच पाई थी, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने ढाई साल के अंदर ही इनमें से लगभग आधे गांवों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपये और कृषि विकास के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये आवंटित किये गए। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में पेट्रोलियम सेक्टर में करीब 35,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। उन्होंने कहा कि राज्य के लगभग 40 लाख लोगों को इन ढाई वर्षों में एलपीजी कनेक्शन मिला है, मुद्रा योजना के माध्यम से लगभग दो लाख करोड़ का लोन युवाओं को दिया गया है, जन-धन योजना के माध्यम से अकेले उड़ीसा प्रदेश में लगभग 84 लाख बैंक अकाउंट खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में आदिवासियों के विकास के लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपये की अलग से व्यवस्था की गई है।

आजादी के 70 साल बाद भी उड़ीसा के लगभग 3474 गांवों में बिजली नहीं पहुंच पाई थी, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने ढाई साल के अंदर ही इनमें से लगभग आधे गांवों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर लिया है।

पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के राज्य सभा में दिए गए संबोधन पर कटाक्ष करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि काले-धन को देश की अर्थव्यवस्था से हटाने के लिए नोटबंदी की योजना से उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि काले-धन और भ्रष्टाचार पर कड़े-प्रहार से कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता, आप पार्टी सब के चेहरे का नूर उड़ गया है, उनमें हाय-तौबा मची हुई है। श्री शाह ने कहा कि 7 तारीख तक समूचा विपक्ष मोदी जी से सवाल करता था कि मोदी जी, आपने काले-धन के लिए क्या किया, 8 तारीख की आधी रात के बाद ये कह रहे हैं कि कालेधन के लिए ऐसा क्यों किया, 'क्या' से 'क्यों' हो गया, मैं तो यह पूछना चाहता हूँ कि आखिर आपका क्या गया, ज़रा देश की जनता को तो बताइये।

भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि मैं उनसे (विपक्ष) से पूछना चाहता हूं कि वे मोदी जी द्वारा काले धन के खिलाफ छेड़े गए अभियान से परेशान क्यों है? श्री शाह ने कहा कि इस मुद्दे पर विभिन्न विचारधाराओं वाली पार्टियों ने हाथ मिला लिया है। जब कभी बाढ़ आती है तो सर्प, नेवला, चूहे, बिल्ली एक साथ एक ही पेड़ पर चढ़ जाते हैं। अब मोदी जी के विमुद्रीकरण की बाढ़ ने विपक्ष और उनके नेताओं- ममता, मुलायम, मायावती और केजरीवाल को एक ही छतरी के नीचे शरण लेने के लिए बाध्य कर दिया है। ये सभी मोदी जी के बाढ़ का पानी (कालेधन के विरुद्ध अभियान) उतरने का इंतजार कर रहे हैं। ■

महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में खिला कमल

गत 8 नवंबर को जब 500 व 1000 के पुराने नोट रद्द करने की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने घोषणा की, उसी दिन से काले-धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्र की भाजपा सरकार की इस मुहिम को देश की जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। विमुद्रीकरण के फैसले के बाद महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की जीत से यह स्पष्ट हो गया है।

महाराष्ट्र में 147 नगर परिषद् के लिए चुनाव हुए, इसमें सीधे नगर अध्यक्ष का चुनाव होता है। इन जगहों पर 2011 में चुनाव हुआ था, तब भाजपा के मात्र 8 नगर अध्यक्ष थे। इस बार के चुनाव में भाजपा को अद्भुत सफलता हासिल हुई, पार्टी के 52 नगर अध्यक्ष चुने गए हैं। ये इलाके कांग्रेस और एनसीपी के गढ़ हुआ करते थे, लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। 147 नगर परिषद् में जो चुनाव हुए, वहां पहले भाजपा के केवल 298 सदस्य हुआ करते थे। इस बार 298 के मुकाबले 980 सीटों पर भाजपा विजयी हुई है, अन्य पार्टियों की सीटें काफी घट गई हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त मतों के प्रतिशत में भी भारी ईजाफा हुआ है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में 27 नवंबर को संपन्न हुए स्थानीय निकाय के कुल 3756 पार्षद सीटों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अब तक घोषित 3298 सीटों में से 963 सीटों पर जीत हासिल कर अन्य प्रमुख पार्टियों को बड़े अंतर से पीछे छोड़ सबसे बड़ी पार्टी बनी है। ज्ञात हो कि पिछली बार

स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा को जीत दिलाने के लिए लोगों को धन्यवाद देता हूं। यह भाजपा की गरीब-समर्थक विकास की राजनीति की जीत है।

—नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षियों को जाग जाना चाहिए। नोटबंदी का फैसला देश हित में लिया गया है।

—अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

यह भाजपा की बड़ी सफलता है क्योंकि राज्य के अलग-अलग हिस्सों में चुनाव हुआ जहां विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाज के हर तबके ने भाजपा को स्वीकार लिया है।

— विजय रूपानी, मुख्यमंत्री, गुजरात

यह जीत महज एक लहर नहीं है। यह एक सुनामी है। भाजपा सरकार ऐसी है जो आम आदमी के बारे में सोचती है। लोगों ने दिखा दिया है कि भाजपा महाराष्ट्र में नंबर वन पार्टी है। हम इस जीत को महाराष्ट्र की जनता को समर्पित करते हैं।

— देवेंद्र फड़णवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

भाजपा 298 पार्षद सीटें जीत तीसरे स्थान पर रही थी।

भाजपा राष्ट्रीय महासचिव एवं महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी सुश्री सरोज पांडेय ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्त्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह के कुशल संगठन कौशल, श्री देवेंद्र फड़णवीस के नेतृत्त्व में महाराष्ट्र में चल रही सरकार एवं प्रदेश भाजपा नेतृत्त्व की सफल नीतियों एवं गरीब, पिछड़े, दलित व किसान के कल्याण के लिए चलाई जा रही प्रभावी योजनाओं की जीत है।

महाराष्ट्र की ही तरह गुजरात में भी दक्षिण गुजरात की कुछ नगर पालिकाओं के चुनाव हुए। सौराष्ट्र में तहसील पंचायत के और उत्तर गुजरात में जिला परिषद् के उप-चुनाव हुए। 125 सीटों पर चुनाव हुए, इसमें भाजपा की 64 सीटें थी जो अब बढ़कर 109 हो गई है। कांग्रेस की सीटें अब 52 से घट कर मात्र 17 रह गई। गुजरात के वापी में नगरपालिका चुनाव में भाजपा ने 44 में से 41 सीटें जीतने में सफलता पाई है। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 03 सीटें ही मिलीं हैं। गोंडल नगरपालिका चुनाव में भी भाजपा ने शानदार जीत हासिल की। भाजपा ने 22 में से 18 सीटों पर विजय प्राप्त की, वहीं कांग्रेस को केवल 04 सीटें मिलीं। वहीं भाजपा ने सूरत के कनकपुर कन्सद नगरपालिका चुनाव में 28 में से 27 सीटें जीत ली। वहीं कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली है।

विभिन्न नगरपालिकाओं की कुल 16 सीटों में भाजपा को 14 और कांग्रेस को केवल दो सीटें मिली। जिला पंचायतों की कुल चार सीटों में दोनों दलों ने दो–दो सीट पर जीत हासिल की। तालुक पंचायत उपचुनावों में भाजपा ने कुल नौ में पांच सीटें जीत ली, कांग्रेस के खाते में चार सीटें गयी। ■

राजस्थान में स्थानीय निकायों के उपचुनाव में भाजपा की जीत

राजस्थान में पंचायत व नगरपालिका के 37 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 19 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को मात्र 14 सीटों पर संतोष करना पड़ा। वहीं स्वतंत्र उम्मीदवार चार सीटों पर विजयी हुए। मोदी सरकार द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा के बाद राजस्थान में हुआ यह पहला चुनाव था। गौरतलब है कि 20 जिलों में हुआ यह उपचुनाव 29 नवंबर को संपन्न हुआ और चुनाव परिणाम 2 दिसंबर को घोषित किए गए। जिला परिषद् की तीन, नगरपालिका की 10 और पंचायत समिति की 24 सीटों पर चुनाव हुए थे। भाजपा के उम्मीदवार बांसवाड़ा और भिलवाड़ा की जिला परिषद् की सीटों पर तथा कांग्रेस के उम्मीदवार जालौर जिला परिषद् की सीट पर विजयी हुए।

पंचायत समिति की 24 सीटों में से भाजपा ने 12 और कांग्रेस ने 10 सीटें जीतीं। स्वतंत्र उम्मीदवार 2 सीटों पर विजयी हुए। नगरपालिका की 10 सीटों में से भाजपा ने 5 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर और स्वतंत्र उम्मीदवार 2 सीटों पर जीत हासिल की।

मनोज तिवारी बने दिल्ली भाजपा के नए अध्यक्ष, बिहार में नित्यानंद राय को मिला दायित्व

भारतीय जनता पार्टी ने श्री मनोज तिवारी को पार्टी की दिल्ली प्रदेश इकाई के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है जबकि बिहार में श्री नित्यानंद राय को अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। फिल्म अभिनेता रह चुके श्री मनोज तिवारी वर्तमान में उत्तर-पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद हैं। मृदुभाषी और विनम्र स्वभाव के चलते वे लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। वहीं, श्री नित्यानंद राय उजियारपुर संसदीय सीट से सांसद हैं। वह इससे पहले 2000, फरवरी 2005, अक्टूबर 2005 और 2010 में लगातार हाजीपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् और भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी महत्वपूर्ण दायित्वों को संभाल चुके हैं। ईमानदार छवि और लंबे समय से पार्टी के लिए काम करने के चलते श्री राय की एक विशिष्ट पहचान है।

भाजपा पत्रिकाओं एवं प्रकाशन विभाग की राष्ट्रीय बैठक संपन्न

'संगठन विस्तार में पार्टी पत्रिकाओं की अहम भूमिका'

नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में 6 दिसम्बर 2016 को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने पार्टी पत्रिकाओं एवं प्रकाशन विभाग की राष्ट्रीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए श्री अमित शाह ने पार्टी प्रकाशन कार्यों और पार्टी पत्रिकाओं के विस्तार की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा एक विचारधारा आधारित पार्टी है और प्रकाशन विभाग पर देश के कोने-कोने तक इसकी विचारधारा को फैलाने की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को शिक्षित किया जाना चाहिए और पत्रिकाओं के माध्यम से पार्टी, केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों में सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए।

भाजपा एक विचारधारा आधारित पार्टी है और प्रकाशन विभाग पर देश के कोने-कोने तक इसकी विचारधारा को फैलाने की जिम्मेदारी है। पार्टी कार्यकर्ताओं को शिक्षित किया जाना चाहिए और पत्रिकाओं के माध्यम से पार्टी, केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों में सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए।

उन्होंने इस अवसर पर नए कलेवर में 'कमल संदेश' और प्रकाशन विभाग के वेब पोर्टल का उद्घाटन किया। प्रकाशन विभाग के सदस्यता अभियान की शुरूआत करते हुए उन्होंने कहा कि सभी पार्टी पत्रिकाओं का उद्देश्य अच्छे विषय-वस्तु प्रस्तुत करने के साथ नए लोगों को पार्टी से जोड़ना भी है। उन्होंने विभिन्न राज्यों से आए सम्पादकों और प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया और प्रकाशन विभाग की जरूरतों पर प्रकाश डाला, जिससे पार्टी पत्रिकाएं पार्टी के प्रभावशाली मुखपत्र बन सकें।

'कमल संदेश' का नया कलेवर रंगीन होने के साथ-साथ इसमें पार्टी गतिविधियों की कवरेज तथा सरकार की उपलब्धियों को लेकर स्पेस में बढ़ोतरी की गई है। पत्रिकाओं में प्रतिभावान सहयोगियों की एक लम्बी सूची है, जिनके लेख विभिन्न विषयों पर छपते हैं और इनमें पार्टी के इतिहास सम्बन्धी विचारधाराओं से लेकर समसामायिक राजनीति सम्बन्धी बहुत उपयोगी लेख रहते हैं, जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी गतिविधियों के महत्व को दर्शाते हैं। आशा है कि इसके वेब संस्करण से वैश्विक पहुंच बढ़ेगी और क्षेत्रीय भाषाओं में राज्यों के पार्टी पत्रिकाओं में निखरती नजर आएगी। वर्तमान में 13 भाषाओं में पार्टी की 20 पत्रिकाएं विभिन्न राज्यों से प्रकाशित हो रही हैं और आशा है कि आने वाले दिनों में प्रकाशन कार्यों पर ध्यान देते हुए प्रकाशनों में वृद्धि की जाएगी।

भाजपा राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री रामलाल जी ने एकात्ममानववाद दर्शन के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर सामग्री देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रहे शताब्दी समारोहों के चलते पं. दीनदयाल उपाध्याय के सभी प्रकाशनों में उनके विचारों तथा उनके दर्शन के लेख प्रकाशित किए जाने चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रत्येक राज्य को उनके विचारों का विस्तार करना चाहिए तथा ऐसी सामग्री प्रकाशित करनी चाहिए जो पाठकों को पार्टी की विचारधारा के बारे में समझा सकें तथा केन्द्र से लेकर राज्य स्तर पर भाजपा की उपलब्धियां प्रस्तुत कर सकें।

प्रकाशन विभाग की गतिविधियों तथा भावी योजना की रिपोर्ट इस बैठक में प्रस्तुत की गई। बैठक में 21 राज्यों के दो-दो प्रतिनिधि तथा 'कमल संदेश' की टीम एवं पार्टी पत्रिकाओं और प्रकाशन विभाग के सदस्य उपस्थित थे। ■

लोकसभा में कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016 पारित

लोकसभा में 29 नवंबर को कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया, जिसमें कालाधन रखने वालों को नोटबंदी के बाद जमा राशि की घोषणा पर कर, जुर्माना तथा अधिभार के रूप में कुल 50 प्रतिशत वसूली का प्रस्ताव किया गया है।

वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने एक दिन पहले आयकर कानून में संशोधन के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। यह आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2016 का संशोधन करने वाला विधेयक 'धन विधेयक' है। संसद में स्पीकर श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि यह सार्वजनिक महत्व वाला विधेयक है। मैं चाहती थी कि इस पर विस्तार से चर्चा हो। मौजूदा स्थिति में चर्चा संभव नहीं लगती। इसलिए मैं विधेयक पर सीधे मत विभाजन करा रही हूं। विधेयक के बारे में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार आयकर अधिनियम में संशोधन लाई है। इसमें प्रावधान है जो लोग अपना अघोषित धन बैंक में जमा कर उसकी जानकारी देते हैं, तो उन्हें 50 प्रतिशत कर, जुर्माना और अधिभार अदा करना होगा। 25 प्रतिशत राशि उन्हें तत्काल मिल जाएगी और शेष 25 प्रतिशत राशि चार साल बाद मिलेगी। श्री जेटली ने कहा कि जो लोग गैरकानूनी तरीके से अघोषित धन रखते पाए गए उन्हें 85 प्रतिशत कर और हर्जाना देना होगा।

उन्होंने कहा कि इससे सरकार को साधन मिलेंगे जिनसे विकास कार्य हो सकेंगे। प्रधानमंत्री ने इसी संबंध में गरीब कल्याण कोष की भी घोषणा की है। विधेयक में प्रस्ताव किया है कि इस अवधि में धन जमा कराने वालों के बारे में यदि यह साबित हुआ कि उन्होंने काला धन रखा है तो उनसे अधिक ऊंची दर और कड़े जुर्माने के साथ कुल 85 प्रतिशत की दर से वसूली की जाएगी। विधेयक पर श्री जेटली ने कहा कि सरकार सत्ता में आने के बाद से कालेधन पर कई कदम उठा चुकी है। उसी क्रम में गत आठ नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को अमान्य करने की घोषणा की थी। इस कदम का उद्देश्य कालेधन पर रोक लगाना और ऐसे धन को मुख्यधारा में लाना है।

गौरतलब है कि चार बार के स्थगन के बाद दोपहर ढाई बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिया। श्री खड़गे ने कहा कि सरकार आयकर संशोधन विधेयक चर्चा के लिए लायी है। उससे पहले नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा लंबित है। उन्होंने कहा, 'हमारी मांग है कि कार्यस्थगित करके नोटबंदी की चर्चा के साथ ही इस विधेयक को भी शामिल कर दीजिए और मिलकर दोनों पर चर्चा हो जाएगी।'

हालांकि बीजद के श्री भतृर्हरि महताब ने कहा कि विधेयक पर चर्चा से पहले सदन में कामकाज सुचारु होना चाहिए। उन्होंने कहा, 'हमारी पार्टी ने और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कालेधन पर सरकार के कदम का स्वागत किया है।' उन्होंने कहा कि इस पर सरकार जो विधेयक लाई है, उसमें कुछ सुधार की जरूरत है। पहले नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और फिर विधेयक पर विस्तार से चर्चा करानी चाहिए।

तृणमूल कांग्रेस के श्री सुदीप बंदोपाध्याय ने भी विधेयक पर चर्चा को नोटबंदी पर चर्चा के साथ मिलाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक चूंकि विमुद्रीकरण (डिमोनेटाइजेशन) का हिस्सा है और उस फैसले के आगे का कदम है, इसलिए दोनों को मिला देना चाहिए। हालांकि अध्यक्ष ने कहा कि विधेयक पर चर्चा को किसी अन्य विषय के साथ नहीं मिलाया जा सकता।

> गत आठ नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को अमान्य करने की घोषणा की थी। इस कदम का उद्देश्य कालेधन पर रोक लगाना और ऐसे धन को मुख्यधारा में लाना है।

इस बीच कांग्रेस के श्री केसी वेणुगोपाल, तृणमूल कांग्रेस के श्री सौगत राय और आरएसपी के श्री एन के प्रेमचंद्रन ने व्यवस्था संबंधी कुछ प्रश्न उठाये। जिन्हें अध्यक्ष ने यह कहते हुए मंजूरी नहीं दी कि सरकार कल विधेयक पेश कर चुकी है और विधेयक को तत्काल पारित कराना आवश्यक है। स्पीकर ने कहा, 'यह सार्वजनिक महत्व वाला विधेयक है। मैं चाहती थी कि इस पर विस्तार से चर्चा हो। उन्होंने विपक्षी दलों से कहा, 'आप चर्चा नहीं चाहते। मैं कुछ नहीं कर सकती।' स्पीकर ने कहा कि विधेयक पर प्रेमचंद्रन, महताब और केसी वेणुगोपाल के कुछ संशोधनों को नियमानुसार राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली है। ■

काले धन पर रोक लगाने हेतु मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदम

केन्द्र की भाजपानीत राजग सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में व्याप्त कालेधन पर प्रभावी रोक लगाने हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सत्ता संभालते ही कालेधन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने अपनी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कालेधन पर नियंत्रण हेतु एक एसआईटी का गठन किया। बतौर वित्त मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार, आयकर विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2016 में की गई तलाशी के दौरान अघोषित आय की स्वीकारोक्ति के एक विश्लेषण के अनुसार, काला धन पैदा करने वाले मुख्य क्षेत्र हैं– विनिर्माण (31 प्रतिशत), रियल एस्टेट (29 प्रतिशत), ट्रेडिंग (8 प्रतिशत), शैक्षिक संस्थान (7 प्रतिशत), ठेकेदारी (6 प्रतिशत), सेवाएं (5 प्रतिशत), रत्न एवं आभूषण (4 प्रतिशत)। गौरतलब है कि राज्य सभा में उठाये गये एक सवाल के जबाब में श्री गंगवार ने 22 नवंबर 2016 को यह कहा। सच तो यह है कि देश–विदेश में काले धन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सत्ता में आते ही और बाद में भी भाजपानीत राजग सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

मोदी सरकार ने नीतिगत पहलों और प्रवर्तन कार्रवाई के जरिए काले धन पर रोक लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जो निम्नलिखित हैं–

- काले धन पर रोक लगाने के लिये माननीय उच्चतम न्यायालय के दो पूर्व न्यायाधीशों की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन।
- खासतौर पर विदेशों में जमा काले धन से निपटने के लिए 'काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर आरोपित अधिनियम, 2015' का पारित होना।
- अन्य बातों के अलावा इस कानून में काला धन छुपाने पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान है, जैसे–काला धन छिपाने पर काले धन की तुलना में तीन गुना कर और कठोर दंड का प्रावधान।
- पनामा कागजात के हालिया खुलासे की जांच के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) के अधिकारियों को मिलाकर एक मल्टी एजेंसी समूह (मैग) का गठन।
- दोहरे कराधान से बचने हेतु हुए समझौते (डीटीएए), कर सूचना विनिमय समझौते (टीआईए) और बहुपक्षीय सम्मेलनों के तहत जानकारी के आदान–प्रदान बढ़ाने के लिए विदेशी सरकारों के साथ लगातार संपर्क।

- स्वतः सूचना आदान–प्रदान (एईओआई) हेतु बहुपक्षीय सक्षम प्राधिकारी समझौते में 'शामिल होना और अमरीका के साथ विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के तहत सूचनाओं का आदान–प्रदान
- अंतरराष्ट्रीय मानकों पर सूचना के आदान–प्रदान हेतु अन्य देशों के साथ डीटीएए पर पुनः समझौता। सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु भारत के साथ हुई संधियों का दायरा बढ़ाने के लिए नए डीटीएए और टीआईए पर हस्ताक्षर।
- मनी लांड्रिंग अधिनियम, 2002 में संशोधन कर वित्त अधिनियम, 2015 के तहत विदेशों में उजागर हुए गैर–कानूनी संपत्ति के बराबर देश में मौजूद संपत्ति की जब्ती।
- 'बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988' में संशोधन कर 'बेनामी लेनदेन (प्रतिषेध) अधिनियम 2016' के तहत बेनामी संपत्ति की जब्ती और सजा का प्रावधान। गौरतलब है कि बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम, 1988 का संशोधन 1 नवंबर 2016 से प्रभावी है।
- प्राप्त सूचनाओं के प्रभावी उपयोग और बेहतर कर अनुपालन के लिए आयकर विभाग द्वारा सूचना तकनीक पर आधारित 'परियोजना इनसाइट' की शुरुआत।
- काले धन पर प्रभावी रोक लगाने, फर्जी करेंसियों को खत्म करने तथा आतंकवादियों के वित्तीय नेटवर्क को समाप्त करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना No.2652 [S.O.3407 (E) द्वारा 8 नवंबर 2016 से 500 व 1000 रुपये की मौजूदा श्रृंखला के बैंक नोटों का चलन बंद।
- आयकर नियम 114बी का संशोधन कर 2 लाख रुपए से ऊपर के किसी भी प्रकार की बिक्री या माल की खरीद या सेवाओं की खरीद के लेन–देन के लिए पैन अंकित करना अनिवार्य। ■

ई-पशु हाट पोर्टल का शुभारम्भ

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने 26 नवंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर ई-पशु हाट (www.epashuhaat.gov.in) पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा देश में पहली बार राष्ट्रीय बोवाईन उत्पादकता मिशन के अंतर्गत ई पशुधन हाट पोर्टल स्थापित किया गया है। यह पोर्टल देशी नस्लों के लिए प्रजनकों और किसानों को जोड़ने मे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस पोर्टल के द्वारा किसानों को देशी नस्लों की नस्लवार सूचना प्राप्त होगी। इससे किसान एवं प्रजनक देशी नस्ल की गाय एवं भैंसों को खरीद एवं बेच सकेंगे।

भारत में विश्व की सबसे बड़ी बोवाईन आबादी है। यहां 199 मिलियन गोपशु हैं जो विश्व की गोपशु आबादी का 14 प्रतिशत है। यहां 105 मिलियन भैंसे हैं, जो विश्व की भैंस आबादी का 53 प्रतिशत है। 79 प्रतिशत गोपशु देशी है और 21 प्रतिशत विदेशी तथा वर्णसंकरित नस्लों के हैं।

गोपशु की 37 नस्लें तथा भैंसों की 13 नस्लें राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक स्रोत ब्यूरो (एनबीएजीआर) से मान्यता प्राप्त है।

देशी बोवाईन नस्लें उष्मा साध्य हैं तथा रोग और चिचड़ा प्रतिरोधी है। यह प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में अच्छी तरह से रह लेती है। कुछ नस्लों में इष्टतम पोषण तथा फार्म प्रबंधन परिस्थितियों में अत्यंत उत्पादक होने की क्षमता है।

भारत की बोवाईन आबादी 60 मिलियन सीमांत, छोटे और मध्यम किसान परिवारों के पास है। इनके पास औसतन दो से तीन दुधारू पशुओं का झुंड है।

किसानों की आय को 2020 तक दोगुना करने की माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना को पूरा करने के लिए पशुपालन से होने वाली आय के हिस्से को बढ़ाने के लिए एक कार्यनीति को अपनाने की आवश्यकता है। ■

पशु व्यापार बाजार से संबंधित कमियां

- कोई प्रमाणिक संगठित बाजार नहीं।
- उच्च आनुवांशिक गुणता वाले रोगमुक्त जर्मप्लाज्म को प्राप्त करना मुश्किल।

ई-पशु हाट का उद्देश्य और लक्ष्य

- पशुधन जर्मप्लाजम के लिए ई-व्यापार बाजार पोर्टल
- किसानों को प्रजनकों के साथ जोड़ेगा।
- जर्मप्लाज्म की उपलब्धता के बारे में वास्तविक समय में प्रमाणिक सूचना।

पोर्टल का ब्यौरा

- किसानों को उन सभी स्रोतों के बारे में जानकारी देगा जहां हिमित वीर्य, भ्रूण तथा जीवित पशु, पशुधन प्रमाणन के साथ उपलब्ध है।
- किसानों को देश के 56 वीर्य केंद्रों (20 राज्यों), 4 सीएचआरएस (4 राज्य तथा 7 सीसीबीएफ (6 राज्य) के साथ जोड़ेगा तथा "किसान से किसान तक" तथा "किसान से संस्थान तक" संपर्क स्थापित करेगा।

किसानों के लिए

- बोवाईन प्रजनकों, विक्रेताओं तथा खरीददारों के लिए वन स्टाप पोर्टल
- ज्ञात आनुवांशिक गुणता के साथ रोगमुक्त जर्मप्लाज्म की उपलब्धता
- बिचौलिए की भागीदारी को कम से कम करना।
- नकुल स्वास्थ्य पत्र से केवल टैंग किए गए पशुओं की बिक्री।
- देश में विविध देशी बोवाईन नस्लों का परिरक्षण।,
- किसानों की आय में वृद्धि।

वैब पोर्टल को खोलने पर किसान जीवित पशु, वीर्य तथा भ्रूण के विकल्प को चुन सकता है, ब्यौरे की तुलना कर सकता है, पूरी सूचना दे सकता है तथा अपनी स्थान पर पशु की डिलीवरी लेने के लिए आनलाइन पैसा अदा कर सकता है।

केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए

- वास्तविक समय में अधिक पारदर्शिता के साथ कार्यक्रम का निरीक्षण।
- विभिन्न मदों की मांग और आपूर्ति संबंधी स्थिति।
- सृजित हुई रिपोर्टों की मॉनीटिरिंग तथा मूल्यांकन।
- प्रजननक निर्देशिका
- सार्वजनिक तथा निजी दोनों सेक्टर की सेवाओं के लिए भंडार तथा एकत्रकर्ता।
- निर्णयों के लिए साक्ष्य आधारित नीतिगत सहायक सूचना।
- राष्ट्र के लिए उत्पादन योजना का पूर्वानुमान तैयार करना तथा उसे लक्षित करना।
- लक्षित आनुवांशिक विकास।
- अवसंरचना तथा शिक्षा की आवश्यकता का आकलन करना।
- डाटा माइनिंग तथा तथा विश्लेषण का प्रयोग करते हुए वैश्विक मान्यता।
- सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण

भारत का ग्रामीण समाज एवं अन्त्योदय

श्री दीनदयाल उपाध्याय गांधीजी के बाद एक प्रमुख आर्थिक चिन्तक रहे हैं। उन्होंने भी व्यावहारिक और गांव व गरीब प्रधान अर्थ व्यवस्था पर जोर दिया। प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं पर लिखी उनकी पुस्तक उस समय विशेष चर्चित हुई थी। उन्होंने पूरे आर्थिक चिन्तन को एकात्म मानववाद की एक नई दिशा दी थी। वे मनुष्य को समग्रता में देखने पर विशेष बल देते रहे।

शान्ता कुमार

भारत गांवों का देश है। करोड़ों भारतवासी छोटे - छोटे गांवों में रहते हैं। इसीलिए भारत की सभ्यता व अर्थ व्यवस्था सदा से ग्रामीण प्रधान रही है।

स्वतंत्रता आन्दोलन के समय देश के नेताओं के सामने ग्रामीण प्रधान भारत का चित्र था। उस समय जब भी स्वतंत्र भारत की कल्पना की जाती थी, तो हमेशा ग्रामीण प्रधान अर्थ व्यवस्था के बारे में सोचा जाता था। एक तथ्य पर हमेशा जोर दिया गया कि भारत की अधिकतर जनसंख्या छोटे-छोटे गांवों में रहती है। उस समय के राष्ट्रकवि श्री सोहन लाल द्विवेदी का यह गीत बहुत प्रसिद्ध था.....

है सच्चा हिन्दुस्तान कहां
वह बसा हमारे गांव में
महान कवि सुमित्रानन्दन पन्त ने भी गाया था.....
भारत माता ग्रामवासिनी

इन्हीं सब बातों का ध्यान रखकर महात्मा गान्धी जी ने ग्रामीण प्रधान अर्थ व्यवस्था की कल्पना की थी। वे बार-बार कहते थे कि स्वतंत्र भारत में देश की प्रगति तभी होगी, यदि अर्थ व्यवस्था गांव से शुरू हो। गांव आबाद होगा तो भारत समृद्ध होगा।

इससे पूर्व भी भारत में गरीबी व पिछड़ेपन के उन्मूलन के लिए देश भक्त विचार करते रहते थे। दादा भाई नौरोजी ने गरीबी के सम्बन्ध में शायद सबसे पहले एक ऐतिहासिक पुस्तक लिखी थी।

आधुनिक भारत के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानन्द की नजरों से भी यह समस्या ओझल नहीं हुई। उन्होंने मोक्ष के लिए घर-बार परिवार सब कुछ छोड़ दिया था। वे तो निर्विकल्प समाधि लेना चाहते थे, लेकिन उनके गुरू स्वामी रामकृष्ण का आदेश था कि उनके स्वर्गवास के बाद वे एक बार भारत का भ्रमण करें और फिर तय करें कि उन्हें क्या करना है। स्वामी विवेकानन्द ने युवा सन्यासी के रूप में दो वर्ष तक भारत का भ्रमण किया। भारत के

लोगों की गरीबी, पिछड़ापन तथा झोंपड़ियों में लाचारी का अन्धेरा देखकर वे आहत हो गए थे। एक ओर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा और दूसरी ओर करोड़ों भारतवासियों की दरिद्रता। भारत भ्रमण के अन्त में विवेकानन्द कन्याकुमारी पहुंचे और समुद्र के बीच की चट्टान पर खड़े होकर ऐतिहासिक घोषणा की.....

''हे प्रभु, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। जब तक भारत का प्रत्येक व्यक्ति भर पेट भोजन नहीं कर लेता तब तक मैं बार-बार जन्म लूँ और भारत माता की सेवा करता रहूं।''

स्वामी विवेकानन्द ने सब कुछ मोक्ष के लिए अर्पित कर दिया था, परन्तु मातृभूमि के लिए उन्होंने उस मोक्ष को भी छोड़ दिया।

गान्धीजी ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर अन्त्योदय की कल्पना की थी। समाज में जो व्यक्ति सबसे पीछे है या पंक्ति में सबसे पीछे रह गया है उसकी चिन्ता सबसे पहले की जानी चाहिए यही अन्त्योदय की भावना थी। उन्होंने जोर दिया था कि स्वतन्त्र भारत के विकास में पहल नीचे से, झोंपड़ी से और गरीबों से की जानी चाहिए।

श्री दीनदयाल उपाध्याय गांधीजी के बाद एक प्रमुख आर्थिक चिन्तक रहे हैं। उन्होंने भी व्यावहारिक और गांव व गरीब प्रधान अर्थ व्यवस्था पर जोर दिया। प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं पर लिखी उनकी पुस्तक उस समय विशेष चर्चित हुई थी। उन्होंने पूरे आर्थिक चिन्तन को एकात्म मानववाद की एक नई दिशा दी थी। वे मनुष्य को समग्रता में देखने पर विशेष बल देते रहे।

वर्षों की साधना के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतन्त्र हुआ। आजादी के जोश में हम कुछ होश खो बैठे। स्वामी विवेकानन्द और महात्मा गांधी भुला दिए गए। बड़े-बड़े नगरों के लिए बड़ी-बड़ी योजनाओं के बड़े-बड़े जश्न होने लगे। नारों की गूंज में कुछ बुनियादी बातें भुला दी गईं। कभी कल्याणकारी राज्य का नारा दिया गया कभी समाजवाद लाने की बात कही गई। फिर समाजवादी समाज की रचना का आश्वासन दिया गया।

देश का विकास तो हुआ पर उसके साथ सामाजिक न्याय न हो सका। विकास का सबसे अधिक लाभ सबसे अधिक सम्पन्न व्यक्ति ने उठाया, कुछ लाभ मध्यम वर्ग के लोगों को मिला। परन्तु समाज के सबसे अधिक गरीब व्यक्ति तक यह लाभ बहुत कम ही पहुंचा।

यही कारण है 57 वर्षों की आजादी के लम्बे सफर के बाद भी आज भारत में 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनकी आय इतनी कम है कि इतने में जीवित रहना भी एक चमत्कार है। हजारों लाखों लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता, चलने को सड़क नहीं, दवाई तथा पढ़ाई का प्रबन्ध नहीं, आजादी का प्रकाश इन झोंपड़ियों के अन्दर के अन्धेरे को छू तक नहीं पाया। आजादी के तुरंत बाद ही ग्राम आधारित योजनाएं, देश के विकास के लिए अधोसंरचना बनाने के बजाए उस समय के सत्ताधारियों की प्राथमिकताएं बदल गईं।

इन सब कारणों से अमीर और गरीब की खाई बढ़ती चली गई। अमीर, और अमीर होता गया तथा गरीब और अधिक गरीब होता गया। बेरोजगारी की समस्या विस्फोटक होती चली गई। असन्तोष सुलगता रहा। युवा पीढ़ी चौराहे पर आती रही, अपराध बढ़ते रहे। जिस प्रकार का विकास हुआ, लेकिन सामाजिक न्याय नहीं मिला उसका यह स्वाभाविक परिणाम है। प्रसिद्ध कवि दिनकर की पंक्ति याद आ रही है.....

शक्ति नहीं तब तक
जब तक सुखभाग न सबका सम हो,
नहीं किसी को बहुत अधिक हो
नहीं किसी को कम हो।

आज इस बात की आवश्यकता है कि विकास की पूरी दिशा को अन्त्योदयमुखी कर दिया जाए। सर्वप्रथम सबसे गरीब व्यक्ति की चिन्ता की जाए तथा उनकी बुनियादी आवश्यकता पूरी की जाए। इसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं, बल्कि इसी धन के प्रावधान से केवल दिशा बदलने से यह सब कुछ किया जा सकता है।

गान्धीजी और दीनदयालजी के प्रति मैं प्रारम्भ से आकर्षित रहा हूं। 1977 में पहली बार हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पर मैंने सारे बजट को गांव और गरीब के प्रति उन्मुख कर दिया था। पीने का पानी देने का काम युद्ध स्तर पर हुआ। तब अन्त्योदय योजना शुरू की। एक लाख उन लोगों को चुना गया जो सबसे अधिक गरीब थे। अतिरिक्त धन का प्रावधान नहीं किया, परन्तु एक आदेश निर्गत किया गया जिसके अनुसार हर योजना सबसे पहले उन एक लाख लोगों के लिए काम करेगी। विकास की गति ऊपर से नीचे की ओर न होकर नीचे से ऊपर की ओर उर्ध्वगामी हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि एक वर्ष में 10 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए थे। पंडितजी कहा करते थे कि विकास एकांगी नहीं होना चाहिए और अधिकार केन्द्रित नहीं होना चाहिए। वे पूरी तरह समाज के सर्वांगीण विकास और समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के जीवन स्तर में सुधार न केवल रहन-सहन बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि सभी क्षेत्रों में भी हो, विचार से कार्य होगा तब कहीं जाकर भारत की जनसमस्याओं का निदान संभव होगा। ■

देश का विकास तो हुआ पर उसके साथ सामाजिक न्याय न हो सका। विकास का सबसे अधिक लाभ सबसे अधिक सम्पन्न व्यक्ति ने उठाया, कुछ लाभ मध्यम वर्ग के लोगों को मिला। परन्तु समाज के सबसे अधिक गरीब व्यक्ति तक यह लाभ बहुत कम ही पहुंचा।

(लेखक हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं।)

(साभारः अंत्योदय विशेषांक)

भाई महावीर नहीं रहे

मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं जनसंघ के संस्थापक सदस्य डॉक्टर भाई महावीर का 3 दिसंबर को नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 94 वर्ष के थे। भाई महावीर अप्रैल 1998 से मई 2003 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। वे लाहौर में 1938 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। सन् 1942 में वे प्रचारक बने। 1951 में जनसंघ की स्थापना के समय वे इसके राष्ट्रीय महामंत्री बने।

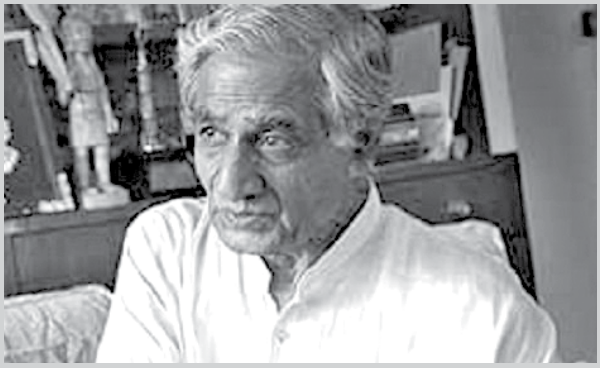

इनके निधन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री ओपी कोहली, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर आदि ने श्रद्धांजलि अर्पित की। ■

@narendramodi

भाई महावीर एक बड़े नेता थे, वह कार्यकर्ताओं की ऐसी पीढ़ी से संबंधित थे जो नि:स्वार्थ राष्ट्र निर्माण की दिशा में खुद को अर्पण करते थे।

उनका निधन पार्टी ही नहीं, संपूर्ण देश के लिए अपूरणीय क्षति

—अमित शाह, *भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष*

भाई महावीर जी अत्यंत कर्मठ एवं विचारों के प्रति प्रतिबद्ध थे, उनका सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र, विचारधारा एवं समाजसेवा के लिए समर्पित रहा। पेशे से प्राध्यापक रहे डॉक्टर भाई महावीर ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी हैं। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संगठन विस्तार में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा लेते थे। डॉक्टर भाई महावीर अप्रैल 1998 से मार्च 2003 के बीच मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। वे दो बार राज्यसभा सदस्य भी रहे। श्री भाई महावीर जी का निधन भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, बल्कि संपूर्ण देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मैं अपनी और पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिवार को सामर्थ्य प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं।''

वे प्रखर विचारक एवं कुशल संगठनकर्ता थे

—प्रो. विजय कुमार मलहोत्रा, *वरिष्ठ भाजपा नेता*

डॉ. भाई महावीर मुहयाल ब्राह्मण थे और अमर बलिदानी भाई मतिदास के वंशज और क्रांतिकारी हुतात्मा भाई परमानन्द के सुपुत्र थे। लाहौर (पाकिस्तान) में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्पर्क में आए और शीघ्र ही सायं शाखाओं के प्रमुख बन गए।

1943 में मेरे स्वयंसेवक बनने से लेकर उनकी मृत्यु तक मेरा उनसे घनिष्टता का संबन्ध रहा। विभाजन के समय स्वयंसेवकों द्वारा मुस्लिम लीग और मुस्लिम पुलिस से हिन्दुओं-सिखों की रक्षा तथा डी.ए.वी. कॉलेज में लगाए गए शरणार्थी कैम्प के संचालन में उन्होंने दिन-रात एक किया। पाकिस्तान बनने के बाद वह दिल्ली आए और संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख बने। गांधी जी की हत्या के पश्चात संघ पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। प्रतिबन्ध के विरोध में संघ द्वारा प्रारम्भ किए गए सत्याग्रह का उन्हें संचालक घोषित किया गया। 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्यक्ष बने तो डॉ. भाई महावीर और पंडित मौलिचन्द्र शर्मा महामंत्री बने थे। डॉ. महावीर दिल्ली भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। लाहौर में डी.ए.वी. कॉलेज और दिल्ली में पंजाब यूनिवर्सिटी कैम्प कॉलेज और बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के डी.ए.वी. कॉलेज में वह प्रोफेसर रहे। आपातकाल में गिरफ्तारी के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। आपातकाल की समाप्ति के पश्चात् उन्हें बहाल किया गया। डॉ. भाई महावीर 1968 से 1974 तथा 1978 से 1984 दो बार राज्यसभा के सदस्य बने और संसद सदस्य के रूप में अपनी अनन्य छाप छोड़ी। डी.ए.वी. कॉलेज सांय के प्रिंसिपल पद से रिटायर होने के उपरान्त वह मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने और राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपनी स्मृतियों को लिखित रूप दिया।

डॉ. भाई महावीर अत्यन्त प्रखर वक्ता, विचारक, संगठन कर्ता और महान शिक्षाविद थे। उनकी मृत्यु से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रीय विचारधारा की अपूरणीय क्षति हुई है।

विमुद्रीकरण का रबी की बुआई पर कोई असर नहीं

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने 2 दिसंबर को कहा कि विमुद्रीकरण का रबी की बुआई पर कोई असर नहीं पड़ा है और 2 दिसंबर तक के आंकड़े के अनुसार रबी की बुआई के रकबे में पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। कृषि मंत्री ने कहा कि देश भर में अब तक कुल रबी फसल की बुआई की स्थिति पिछले साल के 382.84 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 415.53 लाख हेक्टेयर है, जो कि 32.70 लाख हेक्टेयर (8.54 प्रतिशत) से अधिक है।

श्री सिंह ने कहा कि गेहूं फसल की बुआई की स्थिति पिछले साल के 152.56 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 173.93 लाख हेक्टेयर है, जो कि 21.37 लाख हेक्टेयर (14.01 प्रतिशत) से अधिक है। दलहन की बुआई की स्थिति पिछले साल के 99.83 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 112.95 लाख हेक्टेयर है, जो कि 13.11 लाख हेक्टेयर (13.14 प्रतिशत) से अधिक है। तिलहन फसल की बुआई की स्थिति पिछले साल के 64.21 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 70.70 लाख हेक्टेयर है, जो कि 6.49 लाख हेक्टेयर (10.11 प्रतिशत) से अधिक है। उन्होंने कहा कि गेहूं, दलहन और तिलहन रबी की मुख्य फसले हैं और तीनों के बुआई के रकबे में वृद्धि दर्ज की गयी है। धान रबी की मुख्य फसल नहीं है।

कृषि मंत्री ने कहा कि ज्यादातर राज्यों में भी रबी की बुआई के रकबे में वृद्धि हुई है। उदाहरण के तौर पर दो बड़े राज्यों- उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में रबी का रकबा बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल रबी फसल की बुआई की स्थिति पिछले साल के 60.517 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 70.897 लाख हेक्टेयर है, जो कि 10.380 लाख हेक्टेयर (17.15 प्रतिशत) से अधिक है। गेहूं फसल की बुआई की स्थिति पिछले साल के 40.854 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 43.020 लाख हेक्टेयर है, जो कि 2.166 लाख हेक्टेयर (5.30 प्रतिशत) से अधिक है। दलहन की बुआई की स्थिति पिछले साल के 8.560 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 15.170 लाख हेक्टेयर है, जो कि 6.610 लाख हेक्टेयर (77.22 प्रतिशत) से अधिक है। तिलहन की बुआई की स्थिति पिछले साल के 10.093 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 11.317 लाख हेक्टेयर है, जो कि 1.224 लाख हेक्टेयर (12.13 प्रतिशत) से अधिक है।

श्री सिंह ने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में अब तक कुल रबी फसल की बुआई की स्थिति पिछले साल के 60.710 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 81.390 लाख हेक्टेयर है, जो कि 20.680 लाख हेक्टेयर (34.06 प्रतिशत) से अधिक है। गेहूं फसल की बुआई की स्थिति पिछले साल के 24.000 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 37.450 लाख हेक्टेयर है, जो कि 13.450 लाख हेक्टेयर (56.04 प्रतिशत) से अधिक है। दलहन फसल की बुआई की स्थिति पिछले साल के 29.420 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 35.820 लाख हेक्टेयर है, जो कि 6.400 लाख हेक्टेयर (21.75 प्रतिशत) से अधिक है। तिलहन की बुआई की स्थिति पिछले साल के 6.650 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 7.380 लाख हेक्टेयर है, जो कि 0.730 लाख हेक्टेयर (10.98 प्रतिशत) से अधिक है। ■

भारत और स्विट्जरलैंड के बीच सूचना के स्वतः आदान-प्रदान के क्रियान्वयन संबंधी 'संयुक्त घोषणा' पर हस्ताक्षर

विदेशी खातों में जमा काले धन की बुराई को समाप्त करना भाजपानीत राजग सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की ओर से प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष श्री सुशील चंद्रा और स्विट्जरलैंड की ओर से भारत में स्विस दूतावास के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन श्री गिल्स रोड्यूट ने 22 नवंबर को सूचना के स्वतः आदान-प्रदान (एईओआई) के क्रियान्वयन संबंधी 'संयुक्त घोषणा' पर हस्ताक्षर किए। इसके परिणामस्वरूप अब स्विट्जरलैंड में 2018 से खोले गए भारतीय नागरिकों के खातों की वित्तीय लेन-देन की सूचना सितंबर, 2019 और इसके बाद भारत को स्वतः ही मिलना संभव हो जाएगा।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के बिना यूपी का सम्पूर्ण विकास संभव नहीं: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 27 नवंबर को भगवान बुद्ध की धरती कुशीनगर (उत्तर प्रदेश) में आयोजित परिवर्तन रैली को संबोधित किया और भ्रष्टाचार एवं काले-धन पर कार्रवाई का विरोध करने के लिए विपक्ष पर जमकर हमला किया, साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा लागू न करने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार पर भी करारा प्रहार किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी-अभी पिछले दिनों हमने देश से काला-धन और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए अभियान चलाया। आप मुझे बताइए कि भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद किया है कि नहीं किया है, काले धन ने बर्बादी लाई है कि नहीं लाई है? उन्होंने कहा कि हमने देश की जनता से 50 दिन मांगे हैं, अभी 20 दिन बाकी हैं। मैंने पहले ही कहा था कि तकलीफ होगी, लेकिन काले-धन और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने के लिए 500 और 100 के पुराने नोट को बैन करने से बड़े लोगों को बड़ी-बड़ी तकलीफें होगीं, छोटे लोगों को छोटी तकलीफ होंगी लेकिन हमने जनता जनार्दन के आशीर्वाद से यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की ताकत देखिए, कल चीन के अखबारों ने लिखा है कि लोकतंत्र में कोई ऐसा फैसला करने की हिम्मत नहीं कर सकता है, उनको पता नहीं है कि भारत में जनता जनार्दन के कारण ऐसा फैसला करना आसान होता है, मैं जनता-जनार्दन का इस अभियान में सहयोग करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कुशीनगर में उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं आप का प्रधान सेवक होने के नाते भरोसा दिलाता हूं कि कभी भी किसी को परेशान नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि काला-धन बाहर लाने के अभियान में हम लगे हैं, इस कारण हम सभी को थोड़ी तकलीफ होगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सरल नहीं है, इसको लागू करना भी सरल नहीं था, लेकिन आप सभी लोगों के भरोसे ने मुझे इस फैसले को लागू करने का साहस दिया।

प्रधानमंत्री जी ने लोगों से मोबाइल फोन से खरीदारी को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि अखबारों में प्रकाशित मोबाइल प्रयोग की विधि को भाजपा कार्यकर्ता हर दुकान के सामने लगा दें। इसी के साथ नौजवानों, सरकारी कर्मचारियों से आग्रह है कि वह अपने आस-पड़ोस के लोगों को मोबाइल से खरीदारी का तरीका बताएं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश एवं उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान किन परिस्थितियों से गुजरा है, कौन नहीं जानता। उन्होंने कहा कि 2014 में गन्ना किसानों का बकाया 22 हजार करोड़ था, उत्तर प्रदेश की सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें सेवा करने का अवसर दिया तो हमने सबसे पहले गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान किया, अब गन्ना किसानों का बहुत कम बकाया रह गया है। उन्होंने कहा कि हमने एथेनॉल उत्पादन पर जोर दिया, ताकि गन्ना किसानों का चीनी के दाम गिरने के बावजूद कोई नुकसान न हो।

> यूपी की सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि झगड़े शांत हो गए हों, किसानों की चिंता करने की फुर्सत मिल गई हो तो यूपी में फसल बीमा योजना को लागू करें। मुझे नहीं लगता है कि वे कर पाएंगे, उन्हें दिलचस्पी ही नहीं है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के बिना यूपी का सम्पूर्ण विकास संभव नहीं हो सकता, इसके लिए भारत सरकार अरबों, खरबों रुपये खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एम्स, किसानों के लिए फ़र्टिलाइज़र के कारखाने लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब यूरिया के लिए किसानों को रात-रात भर कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बुआई से कटाई तक का बीमा किसानों को केंद्र सरकार दे रही है। इसके बाद भी उत्तर प्रदेश की सपा सरकार किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "यूपी की सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि झगड़े शांत हो गए हों, किसानों की चिंता करने की फुर्सत मिल गई हो तो यूपी में फसल बीमा योजना को लागू करें। मुझे नहीं लगता है कि वे कर पाएंगे, उन्हें दिलचस्पी ही नहीं है।" ■

कालेधन और भ्रष्टाचार पर मोदीजी के प्रहार से देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई ख़त्म होगी: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 30 नवंबर को उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में आयोजित विशाल परिवर्तन रैली को संबोधित किया और यूपी के विकास के लिए राज्य की जनता से यूपी में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की अपील की।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 'परिवर्तन यात्रा' का नाम हमने 'परिवर्तन यात्रा' इसलिए रखा है कि हम उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की परिस्थिति और कानून-व्यवस्था के हालात में परिवर्तन लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विकास का परिवर्तन कर रही हैं, जबकि यूपी की अखिलेश सरकार राज्य में विकास के परिवर्तन को रोक कर बैठी है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने अब तक जाति आधारित राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति के अलावे कुछ भी नहीं किया। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार से उसका मत पूछा तो हमने स्पष्ट कहा कि हम ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि देश की मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए मगर सपा, बसपा और कांग्रेस मानते हैं कि देश में ट्रिपल तलाक होना चाहिए।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, गांव-गरीब-किसान के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आने के पहले यूरिया के लिए किसानों को लाठियां खानी पड़ती थी, आज किसानों के लिए यूरिया की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने यूरिया की नीमकोटिंग कर उसकी कालाबाजारी ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ई-मंडी के जरिये किसानों को उनकी फसल का पूरा लाभ मिलने की व्यवस्था की है, स्वायल हेल्थ कार्ड के जरिये मिट्टी की गुणवत्ता व उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिये बुआई से लेकर खलिहान तक किसानों के फसल को सुरक्षित करने का काम किया गया है, लेकिन यूपी में यह योजना

अभी तक शुरू ही नहीं हो पाई है क्योंकि चाचा-भतीजे में प्रीमियम के कमीशन का झगड़ा हो गया है, अभी तक बीमा के प्रीमियम की एजेंसी भी फाइनल नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि आज यूपी में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। यदि इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो वह समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार है।

श्री शाह ने कहा कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से पहली बार गैस सिलिंडर गांव की गरीब महिलाओं तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि अकेले यूपी में लगभग 35 लाख गरीब महिलाओं के घर से धुआं दूर करने का काम केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि मुद्रा बैंक के माध्यम से देश के चार करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा भाजपा शासित राज्यों से युवाओं का रोजगार के लिए पलायन नहीं होता, जबकि पूर्वांचल से यूपी के युवा राज्य से बाहर रहने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि हम यूपी में एक ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जहां रोजगार के लिए युवाओं को राज्य के बाहर जाने को विवश न होना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पिछली कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार की तुलना में हर साल एक लाख करोड़ रुपये अधिक भेज रहे हैं, हम यूपी में एक ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जो यह पैसा राज्य की गरीब जनता तक पहुंचा सके, बीच में ही विकास के पैसे खा जाने वाली सरकार यूपी में नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो यूपी देखते-देखते देश का सबसे समृद्ध प्रदेश बन सकता है। ■

> यदि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो यूपी देखते-देखते देश का सबसे समृद्ध प्रदेश बन सकता है।

'एलडीएफ और यूडीएफ के 30 साल के कुशासन से केरल के सांस्कृतिक मूल्य खतरे में'

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 5 दिसंबर को कहा कि भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटने वाली ऊंच-नीच की राजनीति में विश्वास नहीं करती। पार्टी दक्षिण भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों के प्रणेता रहे श्री नारायण गुरू जैसे व्यक्तित्वों को अपना आदर्श मानती है। केरल की एलडीएफ सरकार को हिंसा की पक्षधर बताते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए के कार्यकर्ताओं पर जितने हमले होंगे पार्टी उतनी ही मजबूत होगी। श्री शाह भारत धर्म जन सेना पार्टी (बीडीजेएस) के एक साल पूरा होने पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने केरल के कारुकुट्टी पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि श्री नारायण गुरू के आदर्शों पर चलकर एनडीए केरल में बहुमत का आंकड़ा हासिल करेगी।

श्री शाह ने कहा कि बीडीजेएस की स्थापना के पूर्व से ही मैं बीडीजेएस से जुड़ाव रखता हूं। केरल में जिस तरह की राजनीतिक स्थिति 30 साल से बनी हुई है। उसकी वजह एलडीएफ और यूडीएफ का कुशासन रहा है। केरल के सांस्कृतिक मूल्य, समाज सुधार का इतिहास और परंपरा खतरे में थे, ऐसे समय में श्री नारायण गुरू के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी सामने आई और उसका भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ। इससे केरल की मूल संस्कृति के आधार पर राजनीति की राह संभव हुई है। एक साल में ही बीडीजेएस ने ग्रास रूट लेवल पर पकड़ बनाने में सफलता हासिल की है। गत विधानसभा चुनाव में एनडीए की भारतीय जनता पार्टी और बीडीजेएस ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उससे तय है कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एनडीए केरल में बहुमत का रास्ता निश्चित तय करेगा।

> केंद्र में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार ने देश के विकास के लिए ढाई साल में बहुत कुछ किया है। सरकार की कई उपलब्धियां हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ढाई साल के बाद भी सरकार पर एक पैसे के भ्रष्टाचार का भी आरोप नहीं लगा है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि केरल की जनता और राजनीतिक दलों को केरल के इतिहास को याद करना पड़ेगा। 19 वीं सदी के अंत में जिस तरह की सामाजिक विषमता जैसे छूआछूत और ऊंच नीच में केरल जकड़ा हुआ था। उस समय श्री नारायण गुरू के सामाजिक आंदोलन ने अहम भूमिका निभाई और तभी से आधुनिक केरल का निर्माण हुआ।

श्री शाह ने कहा कि गांधी जी मानते थे कि दलितों के उत्थान के लिए काम करने की प्रेरणा उन्हें श्री नारायण गुरू से मिली। अद्वैत का प्रचार करने के साथ साथ श्री नारायण गुरू ने धर्म की सरल व्याख्या की। जब 1920 में त्रिशूत में मंदिर की स्थापना की गई तो

उन्होंने दीपक जलाया। 1922 में जब मंदिर की स्थापना हुई तब प्रतिमा की जगह सत्य, धर्म, प्रेम और दया यह चार शब्द लिखे गए। 1924 में जब मंदिर बनाया तो एक शीशा लगवाया जिसमें यह संदेश था कि ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है। एक नए तरह का तत्व ज्ञान श्री नारायण गुरू ने दिया और अद्वैत के सिद्धांत को केरल के कोने-कोने तक पहुंचाया।

श्री शाह ने कहा कि केंद्र में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार ने देश के विकास के लिए ढाई साल में बहुत कुछ किया है। सरकार की कई उपलब्धियां हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ढाई साल के बाद भी सरकार पर एक पैसे के भ्रष्टाचार का भी आरोप नहीं लगा है। संगठन, शिक्षा और औद्योगिक विकास इन तीन मंत्रों के आधार पर समाज की पुनर्रचना के बारे में श्री नारायण गुरू ने सोचा था। आज इसी रास्ते पर चलकर नरेन्द्र मोदी सरकार ने सर्वसमावेशी विकास का रास्ता अपनाया है। विकास ऐसा हो जो हर व्यक्ति तक पहुंचे और विकास ऐसा हो जिसमें हर व्यक्ति का स्थान हो। तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के बगैर विकास सबके लिए समान हो इस तरह की एक नई शुरुआत श्री नरेन्द्र मोदी ने की है।

एलडीएफ पर निशाना साधते हुए श्री शाह ने कहा कि केरल की सरकार विकास में नहीं, हिंसा में विश्वास रखती है। जबसे केरल की यह सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ताओं पर हमले भी हो रहे हैं और उनकी हत्या भी हो रही है। अगर विजयन जी को लगता है कि हिंसा करने से एनडीए का विकास केरल के अंदर रोक सकेंगे तो उन्हें मालूम नहीं है कि जितनी ज्यादा हिंसा होगी, एनडीए उतना ही ज्यादा फैलेगा, उतना ही ज्यादा मजबूत होगा और उतना ही ज्यादा संघर्ष करेगा। ■

'कतार में खड़े लोगों की तपस्या बेकार नहीं जाएगी'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 3 दिसंबर को पीतल नगरी मुरादाबाद में आयोजित परिवर्तन रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने देश को डिजिटल इंडिया बनाने में मदद करने के लिए कम शिक्षित लोगों को मोबाइल के जरिए भुगतान सिखाने के लिए भी सबको आगे आने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश की गरीबी के लिए अब तक अपनों के विकास के लिए ही काम करने वाली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा की सरकार ही राज्य का पूरा विकास कर सकती है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने डिजिटल इंडिया की ओर कदम बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि यह देश परिवर्तन स्वीकार करने वाला है। गरीब भी परिवर्तन स्वीकार करता है। अमेरिका में आज भी बैलेट पेपर से मतदान होता है, लेकिन भारत ईवीएम मशीन से वोट करता है। जनधन खातों का विरोध करने वाले देख रहे हैं कि अब 20 करोड़ हाथों में रूपे कार्ड है। देश में 40 करोड़ स्मार्ट फोन यूजर्स हैं। करीब 65 फीसदी आबादी 35 साल से कम है। सबको मोबाइल के जरिए भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए आगे आएं। कम शिक्षित वर्ग की मदद करें।

श्री मोदी ने कहा कि मुरादाबाद के पीतल की चमक देश के घर-घर में है, लेकिन उसी मुरादाबाद के एक हजार गांवों में आजादी के 70 साल बाद भी बिजली नहीं थी। हमने देश के 18 हजार गांवों में एक हजार दिन में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। मैं 2009 के बाद आज मुरादाबाद आया हूं, लेकिन मेरे आने के पहले उत्तर प्रदेश के 950 गांव रोशन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारें घोषणा करने के लिए नहीं, योजनाएं बनाकर उन्हें पूरा करने के लिए होती हैं।

उत्तर प्रदेश में रही सपा-बसपा सरकारों पर हमला करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राज्य में अब तक अपनों का विकास करने वाली सरकारें ही रही हैं। इसलिए राज्य का भला नहीं हुआ। भाजपा की सरकार बनी तो पूरा जोर सर्वांगीण विकास पर होगा। विकास ही बच्चों की अच्छी शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार और बुजुर्गों के लिए सस्ती दवा की राह असान करेगा। वहीं घर, बिजली और पानी की सबके लिए उपलब्धता बढ़ेगी। सपा की ओर इशारा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मेरे कोई नेता जी नही हैं। सरकार की मालिक यह सवा सौ करोड़ जनता ही है। यही मेरा हाईकमान है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में गरीबी तभी कम होगी जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इसे दूर किया जाए। यूपी, बिहार, पश्चिम

बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जितनी जल्दी गरीबी दूर की जाएगी। देश को गरीबी से निजात मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि मैंने बनारस से इसलिए चुनाव लड़ा था कि राज्य की गरीबी से लड़ सकूं।

कालेधन के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कहते हुए श्री मोदी ने कहा कि कुछ लोग मुझे गुनहगार ठहरा रहे हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। भ्रष्टाचारियों के दिन पूरे हो रहे हैं। हिंदुस्तान की पाई-पाई पर सवा सौ करोड़ हिंदुस्तानियों का हक है। मैं फकीर हूं, झोला उठाकर चल दूंगा। इसी फकीरी ने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है।

> भ्रष्टाचारियों के दिन पूरे हो रहे हैं। हिंदुस्तान की पाई-पाई पर सवा सौ करोड़ हिंदुस्तानियों का हक है। मैं फकीर हूं, झोला उठाकर चल दूंगा। इसी फकीरी ने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों के जनधन खातों में अपना काला धन जमा करवाने के लिए अमीर उनके पैर पकड़ रहे हैं। गरीब बैंक में जमा धन निकालें नहीं और न ही लौटाएं। बैंकों में जमा धन देश के विकास के काम आएगा। मैं जनधन खाता धारकों से कहना चाहता हूं कि वह इस धन को निकालें या लौटाएं नहीं। किसी के दबाव डालने पर मुझे चिट्ठी लिखें। सरकार इस दिशा में विचार कर रही है कि कैसे वह पैसा गरीबों के काम आए।

कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों पर हमला करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने 70 सालों तक देश को मिट्टी तेल, राशन, गैस, चीनी के लिए कतार में खड़ा रखा। मनी-मनी करने वाले अब मोदी-मोदी कर रहे हैं। हमने आखिरी कतार लगवाई है ताकि अब कभी कतार न लगानी पड़े। इरादे नेक हों तो लोग सब कुछ सहने के लिए तैयार रहते हैं। लोगों ने कतारों में जो तपस्या की है वह बेकार नहीं जाएगी। देश भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहता है। ■

देश सोने की तरह तप कर निखरेगा: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 नवंबर को 'मन की बात' कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से बातचीत की। यह कार्यक्रम का 26वां प्रसारण था। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत में देश के वीर जवानों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार दीवाली पर वे जवानों के साथ हिमालय की चोटियों पर थे। श्री मोदी ने कहा कि जब सारा राष्ट्र सेना के साथ खड़ा होता है, तो सेना की ताकत 125 करोड़ गुना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि देशवासियों ने जो शुभकामनाएं और संदेश भेजे, साथ ही अपनी खुशियों में देश के सुरक्षाबलों को शामिल किया, उसकी एक अद्भुत प्रतिक्रिया थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी आपसे विनती है कि हम अपना स्वभाव ऐसा बनाएं कि कोई भी उत्सव हो, देश के जवानों को हम किसी न किसी रूप में याद करें।

नोटबंदी पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कहा कि आपकी कठिनाइयों को मैं समझता हूं, भ्रमित करने के प्रयास चल रहे हैं फिर भी देशहित की इस बात को आपने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि कभी-कभी मन को विचलित करने वाली घटनायें सामने आते हुए भी, आपने सच्चाई के इस मार्ग को भली-भांति समझा है। श्री मोदी ने कहा कि 500,1000 रुपये और इतना बड़ा देश इतनी करेंसियों की भरमार और ये निर्णय-पूरा विश्व बहुत बारीक़ी से देख रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा देश सोने की तरह तप कर, निखर कर निकलेगा और उसका कारण इस देश का नागरिक है, उसका कारण आप हैं।

जम्मू-कश्मीर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां के प्रधान उनसे मिलने आए, कश्मीर में जो स्कूल जलाए गए, उसकी चर्चा भी हुई। आज मुझे खुशी है कि कश्मीर घाटी से आए हुए इन सभी प्रधानों ने गांव में जाकर के सब लोगों को जागृत किया।

> जम्मू-कश्मीर के हमारे बच्चे उज्ज्वल भविष्य के लिये, शिक्षा के माध्यम से-विकास की नई ऊँचाइयों को पाने के लिये कृतसंकल्प हैं।

इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि कश्मीर के बेटे और बेटियों ने करीब 95 प्रतिशत कश्मीर के छात्र-छात्राओं ने बोर्ड की परीक्षा में हिस्सा लिया। बोर्ड की परीक्षाओं में इतनी बड़ी तादाद में छात्रों का सम्मिलित होना, इस बात की ओर इशारा करता है कि जम्मू-कश्मीर के हमारे बच्चे उज्ज्वल भविष्य के लिये, शिक्षा के माध्यम से-विकास की नई ऊँचाइयों को पाने के लिये कृतसंकल्प हैं। उनके इस उत्साह के लिये, मैं छात्रों को तो अभिनन्दन करता हूँ, लेकिन उनके माता-पिता को, उनके परिजनों को, उनके शिक्षकों को और सभी ग्राम प्रधानों को भी हृदय से

मन की बात की मुख्य बातें

- देश के सुरक्षा बलों के प्रति आपका जो भाव है, वह प्रशंसनीय है।
- देशवासियों ने जो शुभकामनायें-सन्देश भेजे,अपनी ख़ुशियों में देश के सुरक्षा बलों को शामिल किया, उसका एक अद्भुत रिसपॉन्स था।
- देशवासियों ने जिस अनूठे अंदाज़ में यह दिवाली जवानों को समर्पित की, इसका असर वहां हर जवानों के चेहरे पर अभिव्यक्त होता था
- जब सारा राष्ट्र सेना के साथ खड़ा होता है, तो सेना की ताक़त 125 करोड़ गुना बढ़ जाती है।
- मेरी आपसे अपील है कि हम अपना स्वभाव बनाएं, कोई भी उत्सव हो, देश के जवानों को हम किसी-न-किसी रूप में ज़रूर याद करें।
- परीक्षाओं में बड़ी तादाद में छात्रों का सम्मिलित होना इशारा करता है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे विकास की ऊंचाइयों को पाने के लिये कृतसंकल्पित हैं।
- कुछ दिन पहले जब बोर्ड की परीक्षा हुई, तो क़रीब 95 प्रतिशत कश्मीर के छात्र-छात्राओं ने बोर्ड की परीक्षा में हिस्सा लिया।
- आज मुझे ख़ुशी हो रही है कि कश्मीर घाटी से आए हुए इन सभी प्रधानों ने गांव में जाकर के दूरदराज के लोगों को जागृत किया।
- कश्मीर में जो स्कूल जलाए गए थे, उसकी चर्चा भी हुई और जितना दुःख हम देशवासियों को होता है, इन प्रधानों को भी इतनी ही पीड़ा थी
- मैंने 'मन की बात' के लिये लोगों के सुझाव मांगे, एकतरफ़ा ही सबके सुझाव आए, सब कहते थे कि 500,1000 रुपये पर विस्तार से बातें करें।
- जिस समय मैंने ये निर्णय किया था तब भी मैंने सबके सामने कहा था कि निर्णय सामान्य नहीं है, कठिनाईयों से भरा हुआ है।
- मुझे ये भी अंदाज़ था कि हमारे सामान्य जीवन में अनेक प्रकार की नई-नई कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा।
- निर्णय इतना बड़ा है इसके प्रभाव से बाहर निकलने में 50 दिन तो लग जाएंगे, तब जाकर के नॉर्मल अवस्था की ओर हम बढ़ पाएंगे।
- आपकी कठिनाइयों को मैं समझता हूं, भ्रमित करने के प्रयास चल रहे हैं फिर भी देशहित की इस बात को आपने स्वीकार किया है।
- कभी-कभी मन को विचलित करने वाली घटनायें सामने आते हुए भी, आपने सच्चाई के इस मार्ग को भली-भांति समझा है।
- 500,1000 रुपये और इतना बड़ा देश इतनी करेंसियों की भरमार और ये निर्णय-पूरा विश्व बहुत बारीक़ी से देख रहा है।
- हमारा देश सोने की तरह तप कर, निखर कर निकलेगा और उसका कारण इस देश का नागरिक है, उसका कारण आप हैं।
- केंद्र, राज्य, स्थानीय स्वराज संस्थाओं की इकाइयां, बैंक कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस-दिन-रात इस काम में जुटे हुए हैं।
- तनाव के बीच, ये सभी लोग बहुत ही शांत-चित्त रूप से, इसे

देश-सेवा का एक यज्ञ मान करके कार्यरत हैं।
- सुबह शुरू करते हैं, रात कब पूरा होगा, पता तक नहीं रहता है और उसी का कारण है कि भारत इसमें सफल होगा।
- कठिनाइयों के बीच बैंक, पोस्ट ऑफिस के लोग काम कर रहे हैं और जब मानवता के मुद्दे की बात आ जाए तो वो दो क़दम आगे हैं।
- इस महायज्ञ के अन्दर परिश्रम करने वाले, पुरुषार्थ करने वाले इन सभी साथियों का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं।
- जन-धन योजना को बैंक कर्मचारियों ने जिस प्रकार से अपने कंधे पर उठाया था उनके सामर्थ्य का परिचय हुआ।
- फिर से एक चुनौती को उन्होंने लिया है मुझे विश्वास है देशवासियों का संकल्प, सबका सामूहिक पुरुषार्थ, इस राष्ट्र को नई ताक़त बनाएगा।

बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

साथ ही उन्होंने यह भी कहा नोटबंदी का निर्णय सामान्य नहीं है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। मुझे अंदाज था कि हमें सामान्य जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। निर्णय इतना बड़ा है इससे बाहर निकलने में 50 दिन तो लग जाएंगे। ■

नोटबंदी के विरोध का सच

खिसियाये दल सड़क से संसद तक छाती पीट रहे हैं

आम लोगों की दिक्कतों के बहाने कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, वामपंथी दल, राष्ट्रीय जनता दल, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस समेत कई दलों ने विरोध जताने के लिए मार्च निकाले। वामदलों ने तो भारत बंद का नारा दिया था। नोटबंदी के खिलाफ भारत बंद करने का दावा करने वाले तो पश्चिम बंगाल में ही बंद नहीं करा पाए।

| कैलाश विजयवर्गीय |

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हजार-पांच सौ के नोट बंद करने के खिलाफ विरोधी दलों के विरोध-प्रदर्शनों को जनता का समर्थन नहीं मिला। यह अलग बात है कि आम लोगों की दिक्कतों के बहाने कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, वामपंथी दल, राष्ट्रीय जनता दल, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस समेत कई दलों ने विरोध जताने के लिए मार्च निकाले। वामदलों ने तो भारत बंद का नारा दिया था। नोटबंदी के खिलाफ भारत बंद करने का दावा करने वाले तो पश्चिम बंगाल में ही बंद नहीं करा पाए। बंद के दिन पश्चिम बंगाल में सभी कारखानों और दफ्तरों में कामकाज हुआ, बाजार खुले और लोग आम दिनों की तरह अपने काम पर गए। बाजारों में खरीददारी भी हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी तो नोटबंदी के बहाने ऐसे जता रही है जैसे केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्हें कोई बड़ा हथियार मिल गया हो। ममता बनर्जी पूरे देश में केंद्र सरकार के खिलाफ रैलियां कर रही हैं। बनर्जी को तमाम कोशिशों के बावजूद दूसरे दलों की ममता नहीं मिल रही है। जिन दलों के सहारे वह अपनी राजनीतिक हैसियत बढ़ाना चाहती हैं, उन दलों ने उनके मंच की शोभा बनने से इंकार कर दिया। सच तो यही है कि जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार, बीजू जनता के नेता और ओडिशा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक, अन्नाद्रमुक की नेता और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता का साथ भी ममता को इस मुद्दे पर नहीं मिला। कांग्रेस तो इस मुद्दे पर रोजाना अपना रवैया बदलती रही। पहले कांग्रेस ने नोटबंदी का समर्थन किया तो बाद में लगातार विरोध का आलाप गाती रही। कांग्रेस के नेताओं को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि दूसरे सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब कैसे दे। पहले सर्जिकल स्ट्राइल पर भ्रमित प्रतिक्रिया देने की तरह नोटबंदी को लेकर भी कांग्रेस के नेता दिग्भ्रमित लग रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती और आम आदमी पार्टी के संयोजक तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल का नोटबंदी पर विलाप तो जनता को भी समझ में आ रहा है। बसपा की कमरों में भरी माया अब केवल कागज बन कर रह गई है। विरोधी दलों के भारत बंद से जदयू तो पूरी तरह अलग ही नहीं रही, बल्कि नीतीश कुमार ने नोटबंदी का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने बेनामी संपत्ति के खिलाफ भी प्रधानमंत्री के बयान की प्रशंसा की है।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री को सत्ता से बेदखल करने का ऐलान करने वाली ममता को अपने ही राज्य में विपक्षी दलों का साथ नहीं मिला। ममता ने कहा है कि मैं यह शपथ लेती हूं कि मैं मरूं या जिंदा रहूं, लेकिन पीएम मोदी को भारतीय राजनीति से हटाकर दम लूंगी। प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी प्रदर्शन करने का ऐलान करते हुए ममता ने कहा है कि अगर नोटबंदी का फैसला वापस नहीं लिया जाता है तो वह मोदी को सत्ता से हटा देंगी। कम से कम मुख्यमंत्री के पद बैठे किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह बोलना तो शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी पर विपक्षी दलों को निशाने पर लेने के बाद तो कई नेताओं की बोलती बंद हो गई थी। यह तो सभी जानते हैं कि 80 फीसदी से ज्यादा आम लोग नगदी की किल्लत से परेशानी के बावजूद प्रधानमंत्री के नोटबंदी के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल नेताओं की परेशानी के कारण तो उनके अपने कुछ निजी कारण है। रही बात भारत बंद को समर्थन मिलने की तो हर जगह बाजार खुले रहे, वाहन चलते रहे और लोगों ने विरोधी दलों के नारों को पूरी तरह नकार दिया। इसी कारण नोटबंदी के खिलाफ बंगाल बंद के फैसले को वाममोर्चा ने गलत करार दिया है। मोर्चा के अध्यक्ष विमान बोस को भारत बंद का ऐलान करने का अब बहुत मलाल हो रहा है। उन्हें अहसास हो रहा है कि जनता ने बंद को समर्थन क्यों नहीं दिया। अब अपने को कोसते हुए कह भी रहे हैं कि बंद का फैसला

> काले धन के खिलाफ बोलने वाले किसी दल के नेता में इतनी ताकत है कि वह अपनी पार्टी के सांसदों और विधायकों से खातों का हिसाब-किताब मांग सके। ऐसा केवल भाजपा में ही हो सकता है।

गलत था। भविष्य में इससे सबक लेने की जरूरत भी बता रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी ने विमान बोस के इस बयान पर कह रहे हैं कि यह अच्छी बात है कि वाममोर्चा को यह बात समझ में आई कि जनता बंद और हड़ताल से तंग आ चुकी है। वाम मोर्चा तो समझ गया पर तृणमूल कांग्रेस के नेता कब समझेंगे कि देश नोटबंदी के साथ है, विरोध में नहीं। ममता बनर्जी की रैलियां जनता को तो छोड़िए विपक्ष को ही एकजुट नहीं कर पा रही हैं। ममता बनर्जी को विपक्षी दलों का अगुआ बनने और अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा बनने की इच्छा भी पूरी नहीं होने वाली है। कांग्रेस और वामपंथी दलों ने तो पहले ममता बनर्जी को अपनी दीदी मानने से ही इंकार कर दिया है। ऐसे में एकला ही चलना पड़ेगा ममता बनर्जी को।

अब देखिये कांग्रेसी नेताओं की नासमझी के नजारे। जब से नोटबंदी हुई है, रोजाना बयानबाजी तो बदलती रही है साथ ही यह भी भूल गए क्या आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं को नोटबंदी के फैसले के बारे पता था और उससे पहले कई जिलों में जमीन खरीदी गई है। एक तरफ कह रहे हैं कि भाजपा नेताओं को प्रधानमंत्री के फैसले के बारे में पता था, दूसरी तरफ संसद में आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को भी विश्वास में नहीं लिया। कम से कम कांग्रेस के नेताओं को काले धन से जमीन खरीदने का आरोप लगाने से पहले यह तो तय कर लेना चाहिए था कि जब प्रधानमंत्री पर वित्त मंत्री से भी चर्चा न करने का आरोप लगा रहे हैं तो फिर भाजपा नेताओं को नोटबंदी के फैसले के बारे में कैसे पता होगा। दरअसल लगातार चुनावी झटकों के कारण कांग्रेस के नेता दिल बहलाने को फिजूल आरोप लगा रहे हैं। जमीन खरीदने का सच तो यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पिछले साल ही फैसला किया था कि हर जिले में संगठन कार्यालय हो और उसी फैसले के तहत जमीनें खरीदी गईं। कांग्रेस के नेताओं को समझ ही नहीं आ रहा है कि कोई प्रधानमंत्री इस तरह कड़ा से कड़ा फैसला भी लागू कर सकता है। नोटबंदी का विरोध कर रहे दलों के नेताओं को तो कालेधन के खिलाफ प्रधानमंत्री की आगे की मुहिम से और झटका लगने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के सांसदों-विधायकों को अपने खातों की जानकारी देने का कहा है। भाजपा के सभी सांसदों-विधायकों को 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक की खातों की जानकारी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को देनी है। क्या किसी और दल में इतनी ताकत और एकजुटता है। काले धन के खिलाफ बोलने वाले किसी दल के नेता में इतनी ताकत है कि वह अपनी पार्टी के सांसदों और विधायकों से खातों का हिसाब-किताब मांग सके। ऐसा केवल भाजपा में ही हो सकता है।

कांग्रेस की तो चुनावों में भी लगातार बुरी हालत हो रही है। अब तो कांग्रेस के अच्छे दिन आने की कोई उम्मीद भी नहीं है। अच्छे दिनों के कारण ही जनता लगातार भाजपा का समर्थन कर रही है। हाल ही हुए लोकसभा और विधानसभा के उपचुनावों में भाजपा को मध्य प्रदेश और असम में तो जीत मिली ही, पश्चिम बंगाल में भी पार्टी दूसरे नंबर पर पहुंच गई। तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा की सीटें तो जीती हैं, पर दूसरे नंबर रही भाजपा के वोट बैंक में भारी बढ़त हुई है। वाममोर्चा तो तीसरे नंबर पहुंच गया। कूचबिहार लोकसभा सीट पर भाजपा का वोट 16.4 से बढ़कर 28.5 फीसदी हो गया है और तामलुक लोकसभा सीट पर भाजपा को पिछले लोकसभा चुनाव में 6.4 फीसदी वोट मिले थे और अब 15.25 फीसदी वोट मिले हैं। कांग्रेस की सभी जगह जमानत जब्त हो गई। यही वजह है ममता बनर्जी के विरोध की भी। भाजपा की बढ़त से ममता परेशान है। कांग्रेस के नेता अपने बुरे दिनों के कारण और परेशान हो रहे हैं। अगर देश नोटबंदी के खिलाफ होता तो महाराष्ट्र के पहले चरण के नगर परिषद् के चुनावों में भाजपा 147 सीटों में से 57 पर जीत हासिल नहीं होती। नोटबंदी के बाद सभी दलों ने इसे मुद्दा बनाकर यहां चुनाव प्रचार किया था। अब यह तो तय हो गया है कि जनता नोटबंदी के खिलाफ नहीं है, केवल कुछ राजनीतिक दल अपने जमा नोटों को बचाने के लिए संसद और सड़क पर हल्ला मचा रहे हैं। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं।)

प्रेरक पहल शहीद की बेटी की शादी में पिता की भूमिका निभाई शिवराज सिंह चौहान ने

भोपाल जेल ब्रेक कांड में शहीद हुए पुलिसकर्मी रमाशंकर यादव की बेटी सोनिया यादव की शादी 9 दिसंबर को हुई। पिता के शहीदी के दो दिन बाद होने वाली शादी हादसे के बाद की परिस्तिथियों की वजह से टाल दी गई थी। राज्य सरकार के सहयोग से शादी को भव्य तरीके से किया गया। रमाशंकर यादव की बेटी सोनिया की शादी में बारातियों का स्वागत फूल देकर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। साथ ही शिवराज सिंह ने ट्वीट के जरिए दूल्हन सोनिया को बधाई दी और खुद को पिता समान कहकर सोनिया को प्रदेश की बेटी कहा और सरकार की तरफ से सोनिया को सरकारी नौकरी की चिट्ठी भी दी। और साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शहीद की बेटी की शादी की जिम्मेदारी सरकार और समाज की है।

विमुद्रीकरण
काले धन पर कड़ा प्रहार

जिन लोगों ने गरीबों के नाम पर विमुद्रीकरण का विरोध किया, वे अपनी विसम्मति के समर्थन में एक भी तर्क पेश नहीं कर पाए।

डॉ. आर. बालाशंकर

8 नवम्बर 2016 का दिन भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन होगा, जिसे व्यापक वित्तीय क्षेत्र में सुधार के रूप में स्मरण किया जाएगा जैसा कि इससे पहले कभी इतना व्यापक सुधार नहीं हुआ था। अब यह कहा जा सकता है कि यह स्थिति लोगों को किसी प्रकार की संभावित कठिनाई के बिना प्राप्त कर ली गई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बैंकों के सामने कतारें लग गईं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी तेजी से परिवर्तनशील मुद्रा सुधार हुआ और खुदरा क्षेत्र में मांग की अस्थायी गिरावट भी देखने में आई।

एक ही झटके में 86 प्रतिशत अवैध करेंसी संचालन में गिरावट आई और एक ऐसे देश में, जहां अभी तक आधे से ज्यादा जनसंख्या बैंकिंग व्यवस्था से बाहर रही है और स्वभावतः यह अपनी परिश्रम की कमाई को घर में रखते हैं और बैंक में जाने से घबराते हैं। वहां यह स्थिति अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है। 14.90 लाख करोड़ के लगभग 70 प्रतिशत उच्च डिनॉमिनेशन के नोट छिपा कर रखे गए, जिन्हें बैंकिंग व्यवस्था में लाकर राष्ट्रीय धन बनाने का काम करने से बहुत बड़ा काम हुआ है।

जिन लोगों ने गरीबों के नाम पर विमुद्रीकरण का विरोध किया, वे अपनी विसम्मति के समर्थन में एक भी तर्क पेश नहीं कर पाए। इस पर सभी सहमत हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़नी होगी। वे यह भी मानते हैं कि काला धन भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। इससे असमानता और महंगाई तथा करेंसी का अवमूल्यन होता है। यह भी बड़ी चिंता की बात है कि देश में बहुत बड़ी तादाद में नकली मुद्रा का आतंक छाया हुआ है। यह सभी मानते हैं कि नकली मुद्रा के संचालन का शेयर लगभग संचालित कालेधन के बराबर है। इस तथ्य को देखते हुए कि काश्मीर में पिछले दस दिनों से शांति रही और स्कूलों में परीक्षा के लिए शत-प्रतिशत उपस्थिति रही और माओवादियों का चुराया हुआ धन केवल कागजी बन कर रह गया।

प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान की कार्यवाही की सराहना सभी ने की है, जिसे बहुत पहले कर लिया जाना चाहिए था। पूर्व आरबीआई गवर्नरों के सुब्बाराव, रंगाराजन, डा. मेघनाद देसाई तथा डा. सुरजीत भल्ला सहित अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इसे साहसिक कदम की संज्ञा दी है। विरोधी दलों का कहना है कि बैंकिंग व्यवस्था से अनजान दूरदराज क्षेत्रों के लोग इससे अत्यधिक प्रभावित रहे हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि असम सरकार ने दूरदराज के दस लाख से भी अधिक चाय बागान मजदूरों की समस्या को अद्वितीय ढंग से संभाला है।

चाय बागान कर्मचारी परम्परागत रूप से खाताधारक बनना नहीं चाहते हैं। हजारों मीलों में फैले चाय बागान को मजदूरी प्राप्त करने वाले लोग सदियों ने नकद रूप में मजदूरी पाते हैं। असम के मुख्य सचिव श्री वी.के. पीपरसेनिया ने कहा कि जब मोदी जी ने डिमॉनीटाइजेशन और नकद लेन-देन पर प्रतिबंध की घोषणा की तो राज्य सरकार की सबसे बड़ी चिंता चाय बगान कर्मचारियों की थी। उन्होंने कहा कि केन्द्र की मदद से राज्य सरकार से विशेष अनुमति प्राप्त कर चाय बागान के कार्यकर्ताओं को निजी चाय कम्पनियों के सहयोग से उन्हें भुगतान के लिए पर्याप्त धन निकालने की अनुमति प्राप्त की। कम्पनियों को कहा गया कि वे राज्य सरकार के खाते में

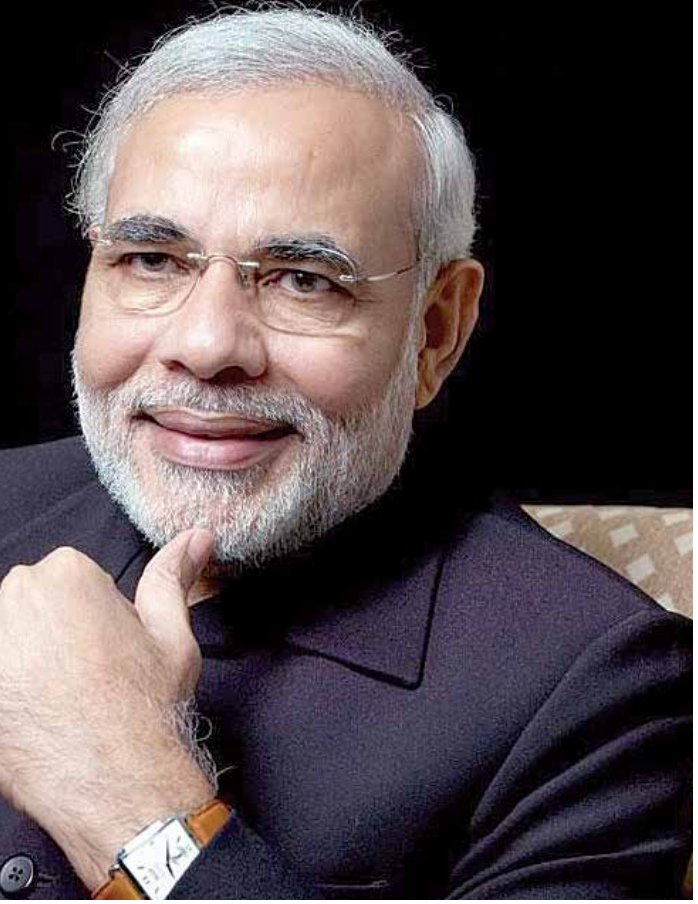

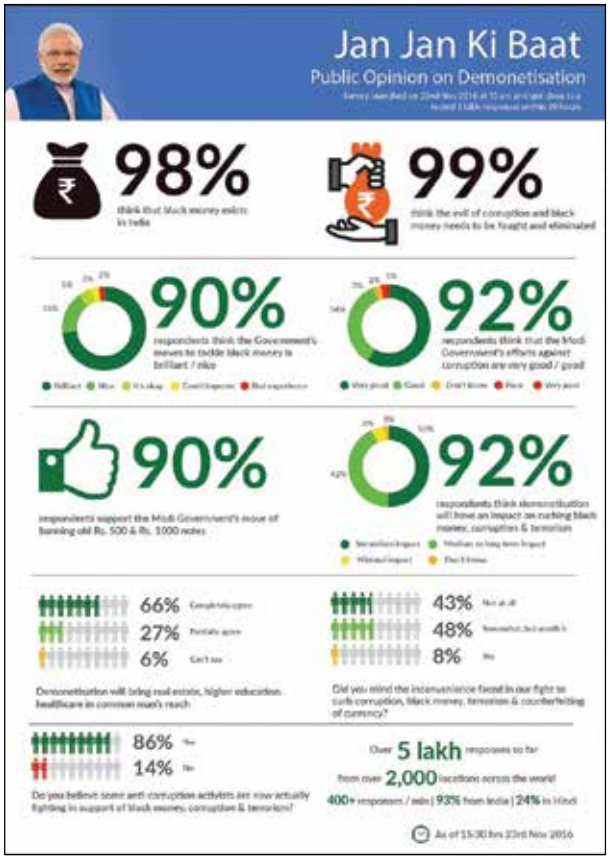

अपना चैक जमा करें और उतनी ही राशि राज्य सरकार ने आहरित की तथा मजदूरों को उनकी मजदूरी वितरित की गई। वास्तव में, पूरे असम में मुद्रा मोर्चे पर स्थिति सामान्य हो गई। अन्य मुख्यमंत्रियों के लिए यह एक अद्भुत उदाहरण है, जो मात्र राजनीतिक एजेंडा के रूप में काले धन से लड़ाई लड़ने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। पीपरसेनिया का कहना है कि जल्द ही ये बैंक खाताधारी बन जाएंगे, जो वित्तीय स्थिति के लिए बहुत बड़ी आगे बढ़ने की छलांग साबित होगी। विभिन्न प्रकार के बैंकों के हजारों से अधिक आउटलेट इन क्षेत्रों में जीवित हो उठेंगे। वास्तव में जन धन योजना के अन्तर्गत स्वतंत्रता के बाद खोले गए खातों की तुलना में पिछले दो वर्षों में ये खाते खोले गए हैं।

यदि लोगों के कल्याण की चिंता है तो विमुद्रीकरण इतिहास में उठाए गए सरकार के ये कदम अत्यंत सराहनीय हैं। जिस समाज में राष्ट्रीय धन का 59 प्रतिशत केवल एक प्रतिशत अमीर लोगों के हाथों में है और 10 प्रतिशत आबादी के पास राष्ट्रीय धन का शेयर केवल 0.2 प्रतिशत रह जाता है और इस प्रकार अमीरों और गरीबों के बीच यह अंतर 2004 और 2014 के बीच 1480 गुणा से बढ़कर 2450 गुणा हो जाता है। यह स्थिति हाल के एक अध्ययन से पता चलती है। नरेन्द्र मोदी ने इस असमानता पर प्रहार किया है। समाज में अस्वीकार्य लेवल की असमानता को खत्म करना होगा और इस दिशा में यह एक ठोस उपाय है।

प्रधानमंत्री की घोषणा में डा. अम्बेडकर की प्रतिबद्धता है जिसे 'सामाजिक और आर्थिक असमानता'' कहा गया है, जिसके साथ ही संविधान में दी गई राजनीतिक असमानता भी शामिल है। इस प्रकार, राजनीति के बड़े धन और काले धन में गिरावट आ जाएगी। इससे राजनीति बेहतर प्रतिभाओं को वापस लाने का आकर्षक क्षेत्र बन सकेगा। इससे कीमतें और उधार दरें नीचे आ जाएंगी। उससे निश्चित ही निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इससे अपराधी और आतंकी गतिविधियों में काले और नकली मुद्रा का उपयोग रूकेगा और आम आदमी का जीवन सुरक्षित बनेगा। काले धन के अभियान से सरकार के खजाने में अधिक राजस्व प्राप्त होगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर कल्याणकारी योजनाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज्यादा खर्च किया जा सकेगा। केपीटेशन फीस के दिन समाप्त हो चुके हैं। बढ़ती हुई वास्तविक कीमतों के वर्तमान स्तर पर बीपीएल परिवारों को सभी घरों तथा 50 मिलियन निःशुल्क गैस कनेक्शन देना संभव नहीं हो सकता है। आज मोदी गरीबों के मसीहा बन गए हैं।

सरकार का रोडमैप संभ्रांत सामाजिक ढांचा खड़ा करना है। उद्देश्य है कि पॉवर ब्रोकर, काला धन और भ्रष्टाचार समाप्त हो और साथ ही धन के समान वितरण पर ध्यान दिया जाए। डिमोनेटाइजेशन सार्वजनिक क्षेत्र व्यय में पारदर्शिता लाने की शुरूआत है और साथ ही इससे बाकी लोगों की कीमत पर कुछेक लोगों द्वारा बुरी तरह खर्च करने की आदत पर भी अंकुश लगाना है। ■

(लेखक पार्टी पत्रिकाएं एवं प्रकाशन विभाग से संबद्ध हैं।)

मृदा स्वास्थ्य कार्ड से मिट्टी की उर्वरकता फिर से प्राप्त करने में मदद मिलेगी

| पांडुरंग हेगडे |

मृदा जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून के अनुसार भारत में पिछले कुछ वर्षों में उर्वरकों, कीटनाशकों और कीटनाशक दवाईयों के अविवेकपूर्ण और अधिक प्रयोग की वजह से प्रत्येक वर्ष 5334 लाख टन मिट्टी खत्म हो रही है। औसतन 16.4 टन प्रति हेक्टेयर उपजाऊ मिट्टी प्रत्येक वर्ष समाप्त हो रही है।

गैर-विवेकपूर्ण तरीके से उर्वरकों के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरकता में कमी आती है, जिसके फलस्वरूप मिट्टी के सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतर पोषक तत्वों में कमी हो जाती है और कृषि पैदावार में भी कमी आ जाती है।

इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पैदावार को बढ़ावा देने के लिए देश भर में मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। "वंदे मातरम्" गीत का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि "सुजलाम और सुफलाम" के सही मायने को चरितार्थ करने के लिए हमें मिट्टी की सेवा और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार लाना आवश्यक है।

मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (एसएचसी) की शुरूआत की। इसके लिए भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय ने पूरे देश में 14 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) जारी करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए अलग से 568 करोड़ रूपये का बजट भी रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य सरकार के सहयोग से इसकी शुरूआत करते हुए प्रत्येक तीन वर्षों में 253 लाख मिट्टी के नमूनों की जांच की जाएगी जिसके फलस्वरूप करीब 14 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) जारी किए जा सकेंगे।

इसके लिए वृहत क्षेत्र में काम करना और जमीनी स्तर पर आंकड़े इकट्ठा करना कठिन कार्य है। फिर भी कृषि मंत्रालय मिट्टी के नमूने की जांच करने और मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष 15 नवंबर तक पूरे देश में 34.47 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) वितरित किए जा चुके हैं।

मिट्टी के नमूनों की जांच में तेजी लाने के लिए सरकार ने मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के तहत 460 नयी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी है। मोबाइल मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के अलावा कृषि मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में 2296 मिट्टी परीक्षण की छोटी प्रयोगशालाओं को काम करने की मंजूरी प्रदान की है। इससे सुदूर इलाकों में मिट्टी के परीक्षण में तेजी आएगी। इससे तकनीकी रूप से कुशल और शिक्षित ग्रामीण

युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

इन मृदा स्वास्थ्य कार्डों से मिट्टी की उर्वरकता में सुधार लाने में कैसे मदद मिलेगी?

इस जांच के पहले चरण में मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, सूक्ष्म पोषक तत्वों और पीएच का पता चल जाएगा। इन बुनियादी जानकारियों का उपयोग कर किसान दूसरे चरण में विशिष्ट खुराक का उपयोग कर मिट्टी की उर्वरकता में सुधार कर पैदावार बढ़ा सकता है। इन कार्डों में किसानों के खेतों की मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की स्थिति के आधार पर सलाह होगी। इसमें मिट्टी की बर्बादी रोकने और मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए किस तरह के मृदा प्रबंधन करने की जरूरत है, इसके बारे में भी सुझाव दिए गए होंगे।

ये कार्ड तीन फसल चक्रों के लिए जारी किये जाएंगे, जिसमें प्रत्येक फसल चक्र के बाद की मृदा की स्थिति दर्ज होगी। इस प्रकार एसएचसी केवल एक फसल चक्र का समाधान नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है, जिससे किसानों को मृदा स्वास्थ्य पर मूलभूत जानकारी उपलब्ध होगी।

गैर-वैज्ञानिक तरीके से खेती करना और उर्वरकों तथा कीटनाशकों के अधिकतम उपयोग से मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो रही और कृषि मृदा अनुपयोगी बनती जा रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता बहुत कम हो जाएगी। उच्च तापमान के कारण मिट्टी में से कार्बनिक पदार्थ कम होने और लगातार मिट्टी के कटाव से बंजर भूमि बढ़ेगी।

इन समस्याओं के समाधान के लिए समस्या का ठोस डाटा बेस तैयार करने की आवश्यकता है। देश भर से एकत्रित मिट्टी के नमूने और मिट्टी की जांच से देश के अलग-अलग पारिस्थितिकीय क्षेत्र में मिट्टी की स्थिति के बारे में वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध होगी। इसके आधार पर मिट्टी की उर्वरकता को दोबारा हासिल करने के उपायों का व्यावहारिक कार्यान्वयन संभव होगा। इससे न केवल लागत कम आएगी, बल्कि किसानों की फसल का उत्पादन भी अधिक होगा और अंततः गरीबी समाप्त करने में मदद मिलेगी।

स्वस्थ मृदा और स्वस्थ भोजन के बीच घनिष्ठ संबंध है। कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग के कारण हमारे देश की मिट्टी बहुत जहरीली हो गई है। जहरीली मिट्टी से उगने वाली फसल से बनाए जाने वाले भोजन से स्वास्थ्य समास्याएं बढ़ेंगी। रसायनिक उर्वरक डालकर हम अधिक पैदावार तो ले सकते हैं, लेकिन उस फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है, जो स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है।

विश्व की 17 प्रतिशत आबादी और भौगोलिक क्षेत्र के मात्र दो प्रतिशत तथा गरीबी के उच्च स्तर के कारण कृषि से जुड़ी 55 प्रतिशत आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा और रोजगार प्रदान करने में मिट्टी की स्थिति में सुधार करना बहुत आवश्यक हो गया है।

> केन्द्रीय कृषि मंत्रालय स्वस्थ मृदा और हरित खेतों के लिए वातावरण तैयार करने के वास्ते राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है, जिससे किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल करने और गरीबी की समस्या का समाधान करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य निकाय एफएओ (खाद्य और कृषि संगठन) ने एसएचसी पहल की सराहना की है। 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के अवसर पर एफएओ के निदेशक जोस ग्रेजियानो ने कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह से कहा था कि खाद्य और संपूर्ण स्वस्थ मृदा सुरक्षा के लिए एसएचसी अन्य देशों के लिए मॉडल हो सकता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'स्वस्थ धरा, खेत हरा' का नारा दिया है, जिसका अर्थ स्वस्थ भूमि और हरित खेत है। स्वस्थ भूमि के लिए हमें स्वस्थ मृदा की आवश्यकता है। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय स्वस्थ मृदा और हरित खेतों के लिए वातावरण तैयार करने के वास्ते राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है, जिससे किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल करने और गरीबी की समस्या का समाधान करने का मार्ग प्रशस्त होगा। ■

**लेखक कर्नाटक में एक स्वतंत्र पत्रकार और स्तंभ लेखक हैं। वे नियमित रूप से पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर लिखते हैं।*

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता नहीं रहीं

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सुश्री जयललिताा का 5 दिसंबर 2016 को निधन हो गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री शाह ने अपने शोक संदेश में कहा, "तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता के निधन का समाचार सुनकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। मैं शोक की इस घड़ी में उनकी पार्टी और समर्थकों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। वह अपनी अंतिम सांस तक तमिलनाडु की जनता के कल्याण के लिए कार्य करती रहीं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके कार्य और राज्य की जनता के प्रति उनका प्यार सदैव याद किया जाएगा। उनके अथक परिश्रम से तमिलनाडु की राजनीति और कार्यशैली में व्यापक परिवर्तन आया है। उनके निधन से अपूरणीय क्षति हुई है। मैं इस मुश्किल क्षण में शांति की प्रार्थना करता हूं।"

'यूरिया के मामले में देश आत्मनिर्भर बनने की ओर'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 26 नवंबर को आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले के टेडपल्लीगुडम में आयोजित विशाल किसान रैली - रायथू महासभा को संबोधित किया और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी द्वारा आंध्र प्रदेश के विकास के साथ-साथ देश के किसानों की भलाई के लिए उठाये गए कई इनिशिएटिव्स पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश भर में फैले पार्टी कार्यकर्ताओं से बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश एवं देश के विकास के लिए आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता को मजबूत करना आवश्यक है।

भाजपा अध्यक्ष ने रायथू महासभा में राज्य भर से आये किसानों का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्त्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ढाई वर्षों से लगातार समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इन ढाई वर्षों में मोदी सरकार ने देश की जनता को एक सर्वस्पर्शीय एवं सर्वसमावेशक विकास देने का व्यापक प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा विकास की अनगिनत योजनाओं में पहली प्राथमिकता किसानों को आगे बढ़ाने की रही है। किसान समागम में आये हुए लोगों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेन्द्र मोदी सरकार किसानों के विकास के लिए सदैव समर्पित रहने वाली सरकार है।

किसानों के लिए शुरू की गई कई योजनाओं की चर्चा करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के माध्यम से आजादी के बाद पहली बार किसानों को उनकी बुआई से लेकर खलिहान व मंडी तक सुरक्षित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने वर्षों से बंद पड़े यूरिया कारखानों को फिर से चालू कर देश को यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर किया है। उन्होंने कहा कि नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत करके प्रधानमंत्री जी ने यूरिया की कालाबाजारी करने वालों, यूरिया को केमिकल इंडस्ट्री में चोरी करके ले जाने वालों एवं किसानों का हक़ मारने वालों को रोककर यूरिया की किल्लत को दूर करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि स्वायल हेल्थ कार्ड के माध्यम से मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ-साथ पैदावार को बढ़ाने के लिए लेबोरेट्री नॉलेज को लैंड तक ले जाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से मोदी सरकार ने हर खेत तक पानी की पहुँच को सुनिश्चित करने का काम किया है।

> राज्य की चंद्रबाबू नायडू सरकार और केंद्र की एनडीए सरकार के अथक प्रयासों से स्पेशल स्टेटस नहीं मिलने से होने वाली सभी कमियों को दूर करके आंध्र प्रदेश के विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है।

श्री शाह ने कहा कि आंध्र प्रदेश के विकास के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रखी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और वाइएसआर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस और वाइएसआर कांग्रेस द्वारा यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस नहीं देने वाली, जबकि कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार ने जिस 14वें वित्त आयोग की नींव रखी थी उसी ने किसी भी राज्य को स्पेशल स्टेटस देने की मनाही कर दी थी। उन्होंने कहा कि मनाही होने के बावजूद राज्य की चंद्रबाबू नायडू सरकार और केंद्र की एनडीए सरकार के अथक प्रयासों से स्पेशल स्टेटस नहीं मिलने से होने वाली सभी कमियों को दूर करके आंध्र प्रदेश के विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग के जरिये आंध्र प्रदेश में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग में राज्यों के शेयर में भी वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि स्पेशल स्टेटस में मिलने वाले टैक्स बेनिफिट की भी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आंध्र प्रदेश के स्पेशल पैकेज में व्यवस्था कर दी है, इतना ही नहीं राज्य के रेवेन्यू डेफिसिट को भी पूरा करने की व्यवस्था कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष आंध्र प्रदेश में मैंने 1,40,000 करोड़ रुपये के कई प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की थी, वे सभी प्रोजेक्ट्स या तो शुरू हो गए हैं या जल्द ही शुरू होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा-नीत एनडीए सरकार और राज्य की तेलुगु देशम-भाजपा सरकार आंध्र प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध है।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। आंध्र प्रदेश का विकास केवल भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी की अगुआई में ही हो सकता है। ■

'मोदीजी के नेतृत्व में हमने देश को एक भ्रष्टाचारमुक्त और पारदर्शी सरकार देने का काम किया है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 27 नवंबर को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित भाजपा ओबीसी मोर्चा रैली को संबोधित किया और राज्य की जनता से कर्नाटक की भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ कर भारतीय जनता पार्टी की गांव, गरीब, किसान, दलित, पिछड़े, महिला एवं युवाओं की भलाई के प्रति समर्पित सरकार बनाने की अपील की। अध्यक्ष जी ने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि नीतीश जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के काले-धन व भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को जो अपना समर्थन दिया है, इसके लिए मैं सार्वजनिक मंच से श्री नीतीश कुमार जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं।

श्री शाह ने कहा कि 2014 के लोक सभा चुनावों में प्रचार के दौरान हमने देश की जनता से यह वादा किया था कि केंद्र में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम इस देश से भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, कल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार के ढाई वर्ष पूरे हो गए, लेकिन इन ढाई वर्षों में हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सके। उन्होंने कहा कि हमने देश को एक भ्रष्टाचारविहीन और पारदर्शी सरकार देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और काला-धन का चोली दामन का साथ होता है। उन्होंने कहा कि 7 नवंबर तक कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता, केजरीवाल - सभी मोदी जी से सवाल करते थे कि मोदी जी, काले-धन पर कार्रवाई के लिए आपने क्या किया और 8 नवम्बर की आधी रात के बाद से ये पूछ रहे हैं कि मोदी जी, काले-धन पर कार्रवाई क्यों की? उन्होंने कहा कि दुःख उनको होता है जिनका काला-धन रद्दी में तब्दील हो गया है। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा, राहुल गांधी, ममता, केजरीवाल - सभी के चेहरे से चमक उड़ गई है, सबके रातों की नींद हराम हो गई है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश के कई राज्यों और केंद्र सरकार में से भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी ने निकाल फेंका है, लेकिन मैं यहां (कर्नाटक) के मुख्यमंत्री की बात करना चाहता हूं, देश में जब भी कहीं काले-धन की बात होती है, छापे पड़ते हैं तो यहां के वर्तमान मुख्यमंत्री का जिक्र जरूर होता है। उन्होंने कहा कि देश में सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार यदि किसी एक प्रांत में है तो वह कर्नाटक में है। उखाड़ कर फेंक दीजिये कर्नाटक से इस भ्रष्टाचारी सरकार को।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। प्रधानमंत्री जी ने देश और देशवासियों का दुनिया में मान-सम्मान बढ़ाने का काम किया है। कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि इन पांच वर्षों में कर्नाटक काफी पिछड़ गया है, उखाड़ कर फेंक दीजिये कर्नाटक से इस भ्रष्टाचारी सरकार को और श्री येदुरप्पा जी के नेतृत्त्व में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइये। ■

पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद बड़ा

पंजाब स्थित अमृतसर में 3-4 दिसंबर को अफगानिस्तान से जुड़े मुद्दों पर छठा 'हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस' संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री समेत विभिन्न देशों के दर्जनों प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद मुख्य मुद्दा रहा और इसमें आतंकवाद को खत्म करने का संदेश देते हुए एक आतंक-विरोधी प्रस्ताव पर सहमति बनी।

आतंकवाद के मुद्दे पर भारत एक बार फिर पाकिस्तान को अलग-थलग करने में कामयाब रहा है। अमृतसर में संपन्न हुई हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद ही मुख्य मुद्दा रहा। कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद को खत्म करने का संदेश देते हुए एक आतंक विरोधी प्रस्ताव पर सहमति बनी। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह रही कि इस प्रस्ताव में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों और हक्कानी नेटवर्क का नाम शामिल किया गया है।

> सभी तरह के आतंकवाद को खत्म किया जाना चाहिए जिसमें आतंकवाद को समर्थन और आर्थिक मदद मुहैया कराना भी शामिल है।

हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस की समाप्ति के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने अमृतसर घोषणा पत्र की जानकारी दी। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है, सभी तरह के आतंकवाद को खत्म किया जाना चाहिए जिसमें आतंकवाद को समर्थन और आर्थिक मदद मुहैया कराना भी शामिल है। हम अफगानिस्तान में तालिबान, आईएसआईएस/दाइश और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे सहयोगी संगठनों द्वारा की जा रही हिंसा को लेकर बहुत चिंतित हैं।'

एकजुटता से आतंकवाद का खात्माः नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमृतसर में 4 दिसंबर को हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर सभी देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद से लड़ाई में सबको एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से

खतराः भारत

अफगानिस्तान की शांति को खतरा है और पूरे क्षेत्र में शांति बहाली की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमा पार से चल रहे आतंकवाद की पहचान करनी होगी और इससे मिलकर लड़ना जरूरी है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के साथ मिलकर छठें हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का उद्घाटन करना हमारे लिए खुशी की बात है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ भारत के करीबी रिश्ते हैं और उसकी मदद करना हमारा मकसद है। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान में शांति लाना चाहते हैं। श्री मोदी ने कहा कि सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि आतंकवाद को आर्थिक सपोर्ट करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी होगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के बढ़ते पंजे से पूरे क्षेत्र को खतरा है। इन हालात में वहां शांति की बात भर करना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। ये कदम सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ नहीं, बल्कि उन्हें शरण देने वालों और फंड मुहैया कराने वालों के भी खिलाफ होने चाहिए।

सम्मेलन में अफ़ग़ानिस्तान के राष्ट्रपति श्री अशरफ़ गनी ने कहा कि एक अफ़ग़ान तालिबान नेता ने बताया कि पाकिस्तान में पनाह न मिले तो वो एक महीना भी नहीं टिक सकते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज़ शरीफ़ के विदेश मामलों के सलाहकार श्री सरताज अज़ीज से मुख़ातिब होते हुए उन्होंने कहा कि कहा कि जो 500 मिलियन डॉलर आप अफ़ग़ानिस्तान को दे रहे हैं वो पाकिस्तान में अतिवाद के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है।

गौरतलब है कि विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के अस्वस्थ होने के कारण वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने घोषणा का उल्लेख करते हुए कहा, "आतंकी संगठनों अल कायदा, दाएश (इस्लामिक स्टेट) और उसके अनुषंगी संगठनों समेत तालीबान के कारण अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर हिंसा से हम बराबर चिंतित हैं।"

वित्त मंत्री ने कहा, "आतंकवाद की समाप्ति सुनिश्चित करने के लिए हम मजबूती से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग करते हैं जिसमें हार्ट ऑफ एशिया क्षेत्र में आतंक के स्वर्ग को खत्म करने के साथ-साथ आतंकवाद के लिए वित्तीय और सभी तरह के तार्किक समर्थन को बाधित करना शामिल हैं।''

> इस प्लेटफॉर्म का मकसद का अफगानिस्तान और उसके पड़ोसी देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और रक्षा को लेकर आपसी सहयोगी बढ़ाना है।

क्या है हार्ट ऑफ एशिया?

यह वार्षिक सम्मेलन कई चुनौतियों का सामना कर रहे अफगानिस्तान पर इस्तांबुल प्रॉसेस का हिस्सा है, जो 2011 में शुरू की गई थी। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, सउदी अरब, ताजिकिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान और यूएई शामिल हैं। इस प्लेटफॉर्म का मकसद का अफगानिस्तान और उसके पड़ोसी देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और रक्षा को लेकर आपसी सहयोग बढ़ाना है। कनाडा, डेनमार्क, मिस्र, फ्रांस, फिनलैंड, जर्मनी, इराक, इटली, जापान, नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन और अमेरिका ने इस पहल का समर्थन किया है। ■

प्रधानमंत्री ने सभी भाजपा विधायकों व सांसदों से अपने खातों का ब्यौरा देने को कहा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 नवंबर को भाजपा के सभी सांसदों और विधायकों से कहा कि वे 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच अपने बैंक खातों के लेनदेन का विवरण भाजपा श्री अध्यक्ष अमित शाह को एक जनवरी तक को सौंप दें। श्री मोदी ने ये निर्देश भाजपा संसदीय दल की बैठक में दिया। भाजपा नेताओं को इस ब्यौरे में अपना नाम, लोक सभा या विधान सभा का क्षेत्र, किस बैंक में खाता है, कुल कितने खाते हैं, खाता का प्रकार, खाता नंबर, खाते में कुल पैसे, 9 नवंबर से 31 दिसंबर तक जमा रकम और निजी या व्यावसायिक आमदनी की पूरी जानकारी देनी होगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर को बड़े नोटों को अमान्य करने के फैसले की घोषणा की थी।

प्रधानमंत्री ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में कहा कि आयकर संशोधन विधेयक कालेधन को सफेद करने के लिए नहीं, बल्कि गरीबों से लूटे गये धन का उपयोग उनके कल्याण के लिए करने के वास्ते हैं। गरीब कल्याण योजना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इस योजना के तहत गरीबों को बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति करने, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, पेय जल आदि मुहैया कराने के लिए धन का उपयोग करेगी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार भारत को नकदविहीन समाज बनाने के लिए प्रत्यनशील है। उन्होंने डिजिटल, मोबाइल अर्थव्यवस्था बनाने के उनके प्रयासों को सभी से समर्थन देने का आग्रह किया। इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने पार्टी सांसदों से कहा कि वे अपने अपने क्षेत्र के पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं अन्य स्थानीय निकायों के कारोबारियों को नकदविहीन लेनदेन अपनाने को प्रेरित करें। ■

जीवेम शरदः शतम!

जन्म दिवसः 25 दिसंबर

पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर कमल संदेश परिवार उन्हें शुभकामनाएं अर्पित करते हुए यह कामना करता है कि वे चिरकाल तक पार्टी एवं राष्ट्र का मार्गदर्शन करते रहें।

आज ही लीजिए

कमल संदेश

की सदस्यता

और

दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता					
	एक वर्ष	₹350/- ☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/- ☐	
	तीन वर्ष	₹1000/- ☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/- ☐	

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास-कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2015-17
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2015-17

डिजिटल लेन–देन को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल इंसेंटिव्स

उपनगरीय रेल नेटवर्क पर 1 जनवरी 2017 से मासिक या सीजनल टिकट की खरीद के लिए डिजिटल भुगतान करने पर 0.5% की छूट

फायदे:

- उपनगरीय रेलवे पर मासिक या सीजनल टिकट लेने वाले लगभग **80 लाख** यात्रियों को फायदा होगा
- यात्रियों द्वारा डिजिटल भुगतान करने से निकट भविष्य में प्रति वर्ष **1,000 करोड़ रुपये** की नकदी की आवश्यकता कम हो जाएगी